

Discover your divinity with us
A/C Showroom
ज्ञान गंगा ॐ मूर्ति माला केन्द्र
उजाला भवन स्टेशन रोड, दुर्ग
0788-4030383, 3293199
भगवान के चरित्र, श्रृंगार
मूर्तियां एवं समस्त
पूजन सामग्री
संगमरमर व पीतल की
मूर्तियां राशि रत्न
एवं उपरतन उपलब्ध

राष्ट्र एवं राज्य के प्रगति पथ पर...

समय



रायपुर एवं दुर्ग से प्रकाशित

दर्शन

दुर्ग शहर में
सुप्रसिद्ध
ज्योतिषाचार्य
पं. एम.पी. शर्मा/
मो. 8109922001
फीस 251/- मात्र
पता:- श्री दुर्गा ज्योतिष कार्यालय
सिकोला भाटा, सब्जी मार्केट के
सामने, धमपा नाका, दुर्ग

संस्थापक : स्व. श्रीमती निलिमा खड़तकर

निष्पक्ष निर्भीक खबरों के साथ

वर्ष 15, अंक 103 पृष्ठ 8, मूल्य 3.00 रुपये

दुर्ग, बुधवार 25 फरवरी 2026

www.samaydarshan.in

बजट में खास

- रायपुर, भिलाई व दुर्ग स्टेट कैपिटल रीजन के लिए 68 करोड़
- रायपुर, भिलाई व दुर्ग मेट्रो रेल परियोजना पर आगे बढ़ेगा काम
- भिलाई में व्यावसायिक परिसर निर्माण हेतु 10 करोड़
- नवा रायपुर में चित्रोत्पला फिल्म सिटी तथा ट्रायबल एवं कल्चरल कन्वेंशन सेंटर निर्माण हेतु 350 करोड़
- हर साल होगा नवा रायपुर में साहित्य उत्सव
- घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में राहत देने 800 करोड़ का प्रावधान
- बीपीएल उपभोक्ताओं को निशुल्क बिजली देने 354 करोड़ का प्रावधान
- बस्तर-सरगुजा ओलंपिक के लिए 5-5 करोड़
- नक्सल प्रभावित रहे अबुझमाड़ व जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी के लिए 100 करोड़
- डिजिटल भारत निधि योजना तहत प्रदेश में लगे 500 मोबाइल टॉवर
- बस्तर में इंटरनेट सेवा बनाए रखने बस्तरनेट परियोजना, 5 करोड़
- 250 महतारी सदन बनाने 75 करोड़
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 2 हजार करोड़

नई पहल

इस वर्ष प्रस्तुत की गई नई पहलें राज्य की उभरती हुई प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक विकास के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती हैं। इन पहलों का उद्देश्य नई संभावनाओं की पहचान कर राज्य की समावेशी प्रगति एवं आर्थिक उन्नति की दिशा में निर्णायक कदम उठाना है।

1. अबुझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी

अबुझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी की स्थापना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य नक्सलवाद के गढ़ कहे जाने वाले अबुझमाड़ और जगरगुंडा को शिक्षा के केंद्र बिन्दु के रूप में विकसित करना है।

2. नए औद्योगिक पार्क

राज्य में 23 नए औद्योगिक पार्क स्थापित करने हेतु 250 करोड़ का प्रावधान है, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

3. लैंड बैंक विकास योजना

लैंड बैंक विकास योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ताकि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।

4. बस्तर एवं सरगुजा में औद्योगिक विकास

खाद्य, Agro Forestry, कृषि एवं कृषि संबद्ध उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

5. इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर 2.0

राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर 20 की स्थापना के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है।

6. सिरपुर विकास योजना

सिरपुर विकास योजना के अंतर्गत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन विरासत के संरक्षण एवं विकास हेतु 42 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

‘ज्ञान’, ‘गति’ के बाद ‘संकल्प’ ...

चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का बजट...

रायपुर। विधानसभा में आज वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी ने ‘संकल्प’ थीम के साथ वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ का अनुमानित बजट पेश किया। उल्लेखनीय है कि चौधरी ने अपना पहला बजट ‘ज्ञान’ व दूसरा ‘गति’ थीम के साथ प्रस्तुत किया था। अपने बजट भाषण में चौधरी ने कहा कि ‘विकसित छत्तीसगढ़ 2047’ हमारा दीर्घकालिक लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए हमने 2030 के मध्यकालिक लक्ष्य को भी निर्धारित किया है। हम एक स्पष्ट रोड-मैप के साथ इस आगे बढ़ रहे हैं। इसी पथ पर हमारा प्रत्येक बजट आगे बढ़ता हुआ एक-एक कदम है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि हमारे विकास यात्रा का केन्द्र बिंदु ‘ज्ञान’ रहा है, जिसके उद्धान के लिए ‘गति’ की रणनीति पिछले बजट में अपनायी गई थी। ‘ज्ञान’ के कल्याण के लिए इस बार हमारे बजट का थीम ‘संकल्प’ है, जो कि जनता जनार्दन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को निष्ठा को समर्पण और दृढ़संकल्प को रेखांकित करता है। कोई भी लक्ष्य पूरा होता है ‘संकल्प’ से। क्षमता कम या ज्यादा हो लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो, संकल्प मजबूत हो, तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। ‘संकल्प’ का आशय है समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अन्वयोदय, लाईवलीहुड एवं पॉलिसी से परिणाम तक। वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास की गति को और तेजी प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रदेश के सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो। भविष्य के अनुरूप कार्यबल तैयार हो। आजीविका के नए अवसर उपलब्ध हों। कमजोर वर्ग अग्रणी बनें और छत्तीसगढ़ के युवाओं को आधुनिक कौशल से उन्नत किया जा सके। चौधरी ने कहा कि सरकार के पिछले 2 बजट के मार्गदर्शी सिद्धांत लक्ष्य (गरीब, युवा, अन्रदाता, नारी) और GATI (Good Governance, Accelerating Infrastructure, Technology, Industrial Growth) थे। इस वर्ष का बजट ऋद्धिग्रहक यह दर्शाता है कि सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल शिक्षा के लिए कुल बजट का 13.5 प्रतिशत संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पहला बजट ज्ञान और दूसरा बजट गति की थीम पर आधारित था, जबकि इस वर्ष का बजट संकल्प की भावना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में समावेशी विकास, अधोसंरचना सुदृढीकरण, निवेश संवर्धन, कुशल मानव संसाधन निर्माण, लाइवलीहुड, अन्वयोदय तथा पॉलिसी से परिणाम तक की स्पष्ट रणनीति को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप प्रवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मिशन मोड में कार्य करने के लिए पांच मुख्यमंत्री मिशन प्रारंभ कर रही है, जिनमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शामिल हैं।



राजकोषीय संकेतक

- राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) वर्ष 2025-26 में 6,31,290 करोड़ संभावित है जो वर्ष 2026-27 में 12.4 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 7,09,553 करोड़ अनुमानित है।
- राज्य की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में 1,62,848 थी, जो 2025-26 में 10.07 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 1,79,244 अनुमानित है।
- वर्ष 2025-26 के लिए कुल प्रारितियों 1,65,100 करोड़ अनुमानित थी, जो वर्ष 2026-27 के बजट में बढ़कर 1,72,000 करोड़ अनुमानित है।
- वर्ष 2025-26 का बजट आकार 1,65,000 करोड़ था, जबकि वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ अनुमानित है। यह दर्शाता है कि व्यय में वृद्धि, प्रारितियों के अनुरूप संतुलित है।
- राजस्व व्यय वर्ष 2025-26 में 1,38,196 करोड़ अनुमानित था, जो वर्ष 2026-27 में 1,45,000 करोड़ अनुमानित है। यह वृद्धि सामाजिक योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के विस्तार को दर्शाती है।
- वर्ष 2026-27 में 26,500 करोड़ का पूंजीगत व्यय अनुमानित है, जो कुल बजट का 15.1 प्रतिशत तथा GSDP का 3.7 प्रतिशत है। यह राज्य की अधोसंरचना निर्माण के लिए निरंतर प्राथमिकता को दर्शाता है।
- द्वितीय घाटा वर्ष 2026-27 में 20,400 करोड़ अनुमानित है। यह GSDP का 2.87 प्रतिशत है, जो FRBM अधिनियम के 3 प्रतिशत के मानक के भीतर है।
- द्वितीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य का राजस्व घाटा 2,000 करोड़ अनुमानित है।

और विकास का प्रभाव हर नागरिक और हर क्षेत्र तक पहुंचे। यह एक संतुलित अग्रणी को दर्शाता है जहाँ आर्थिक विस्तार, सामाजिक न्याय, आधारभूत संरचना निर्माण और सांस्कृतिक पहचान सभी एक साथ आगे बढ़ें। चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने अपने 25 वर्ष पूर्ण करते हुए रजत जयंती वर्ष को ‘अटल निर्माण वर्ष’ के रूप में मनाया। इस अवधि में प्रदेश ने आर्थिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है। इसका प्रमाण है कि राज्य निर्माण के समय जहाँ प्रदेश का बजट मात्र 4 हजार 944 करोड़ था, वहीं आज यह 35 गुना बढ़कर 1 लाख 72 हजार करोड़ तक पहुँच चुका है। यह बजट सर्वस्पर्शी है जो

समाज के सभी वर्गों, महिला, किसान, युवा, उद्यमी की महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। बजट के माध्यम से हमने एक ईमानदार प्रयास किया है कि छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास की गति और तेज हो तथा प्रदेश की इस विकास यात्रा में सभी वर्ग और सभी क्षेत्रों का योगदान हो। SANKALP की थीम पर आधारित यह बजट मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार की 3 करोड़ प्रदेशवासियों के प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है। चौधरी ने अंग्रेजी के शब्दों को स्पष्ट करते हुए कहा कि SANKALP का प्रत्येक अक्षर बजट के मूल आधार स्तंभों

का संयोजन है। S (एस) यानी समावेशी विकास। समावेशी विकास केवल आवश्यकता नहीं, बल्कि आज के छत्तीसगढ़ की प्रगति का मूल सिद्धांत है। यह बजट सुनिश्चित करता है कि विकास क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करते हुए हर समुदाय, विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, किसानों, युवाओं और महिलाओं तक पहुँचे। A (ए) यानी अधोसंरचना। सड़क, सिंचाई, बिजली, शहरी विकास और डिजिटल कनेक्टिविटी के क्षेत्रों में अधोसंरचना निर्मित करने हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। मजबूत आधारभूत संरचना आर्थिक विकास की रीढ़ है और यह राज्य की जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाएगी। N (एन) यानी निवेश। बजट औद्योगिक विकास और निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। नीतिगत सहयोग, प्रोत्साहन, और ईज ऑफ बिजनेस के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों और रोजगार सृजन में तेजी लाई जाएगी। K (के) यानी कुशल मानव संसाधन। बजट में शिक्षा कौशल विकास और क्षमता निर्माण पर विशेष बल दिया गया है, ताकि युवा, स्वास्थ्य, उद्योग, आईटी, पर्यटन, नये उभरते क्षेत्रों में रोजगार मूलक कौशल प्राप्त कर सकें। यह पहल राज्य के मानव पूंजी आधार को और मजबूत बनाएगी। I (ए) यानी अन्वयोदय। कमजोर और वंचित वर्गों के लिए लक्षित कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। सामाजिक सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता को प्राथमिकता दी गई है। L (एल) यानी लाइवलीहुड। कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्र, हस्तशिल्प एवं ग्रामीण उद्यमों को सुदृढ़ और आधुनिक कर, आजीविका के नए अवसर सृजित करने तथा आय बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। बस्तर एवं सरगुजा में आजीविका के साधनों को सशक्त करने के लिए विशेष प्रावधान किये गये हैं। P (पी) यानी पॉलिसी से परिणाम तक। बजट Intent, Initiative, Implement और Impact के मॉडल पर आधारित है, जिसके माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में Reforms को चिन्हांकित कर, उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है।

2026-27 का बजट ‘संकल्प से सिद्धि’ का रोडमैप-मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास, अन्वयोदय और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण के संकल्प को साकार करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का पहला बजट ज्ञान और दूसरा बजट गति की थीम पर आधारित था, जबकि इस वर्ष का बजट संकल्प की भावना को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है, जो विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में निर्णायक कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में समावेशी विकास, अधोसंरचना सुदृढीकरण, निवेश संवर्धन, कुशल मानव संसाधन निर्माण, लाइवलीहुड, अन्वयोदय तथा पॉलिसी से परिणाम तक की स्पष्ट रणनीति को प्राथमिकता दी गई है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप प्रवेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार मिशन मोड में कार्य करने के लिए पांच मुख्यमंत्री मिशन प्रारंभ कर रही है, जिनमें मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन शामिल हैं।

इन मिशनों के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा, नई धार और नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए स्कूल शिक्षा के लिए कुल बजट का 13.5 प्रतिशत प्रावधान किया गया है, जो सर्वाधिक है। बस्तर के अबुझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएगी, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार सुविधा हेतु भी बजट में प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 23 नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना हेतु 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में 200 करोड़ रुपए तथा भूमि विकास बैंक के लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि क्षेत्र राज्य की अर्थव्यवस्था की आधारशिला है। इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 13 हजार 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को 3100 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से धान खरीदी के अंतर्गत की राशि का भुगतान एकमुश्त करने की व्यवस्था जारी रहेगी



और इसके लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में खाद्य, कृषि और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बकरी पालन, सूअर पालन और मधुमक्खी पालन जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंद्रावती नदी पर देवगांव और पटना बराज निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जिससे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का विस्तार होगा और किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माओवादी उन्मूलन में बस्तर फाइटर्स की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए बस्तर फाइटर्स में 1500 नई भर्तियों का प्रावधान किया गया है। पर्यटन और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए होमस्टे योजना हेतु 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य और कनेक्टिविटी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, जिनमें कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन, जगदलपुर-अंबिकापुर हवाई सेवाओं का विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के आयोजन शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करने हेतु व्यापक दक्षता बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं। साथ ही युवाओं के शैक्षणिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी तथा लखपति दीर्घियों के भ्रमण कार्यक्रम के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस बजट को प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब बताते हुए वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी एवं उनकी पूरी टीम को बधाई दी और कहा कि यह बजट प्रदेश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मील का पत्थर साबित होगा।

फ्लैगशिप योजनाएँ

कृषक उन्नति योजना

कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य खेती में आधुनिक तकनीक, बेहतर इनपुट और उत्पादकता बढ़ाने के साथ-साथ फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। महतारी वंदन योजना



महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को

आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह योजना महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना



मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु 6,500 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को चावल, चना, शक्कर और नमक उपलब्ध कराना है। ऊर्जा सब्सिडी



5 एचपी तक के कृषि

पंपों वाले किसानों को मुफ्त बिजली हेतु 5,500 करोड़, ल बत्ती कनेक्शन वाले परिवारों को मुफ्त बिजली हेतु 354 करोड़ तथा घरण उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल हेतु 800 करोड़ सहित कुल 6,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)



ग्रामीण क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना



सभी नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करने हेतु शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 1,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। पीएम जनमन योजना

- विशेष पिछड़े जनजातियों समूहों (PVTGS) के विकास हेतु पीएम जनमन योजना अंतर्गत 720 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- जल जीवन मिशन 3 हजार करोड़
 - राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 2 हजार करोड़
 - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 हजार 725 करोड़
 - समग्र शिक्षा अभियान-1 हजार 500 करोड़
 - प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 825 करोड़
 - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 820 करोड़
 - दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना- 600 करोड़
 - समग्र विकास योजना (ग्रामीण विकास) 300 करोड़

संक्षिप्त समाचार

प्रस्तुत बजट छत्तीसगढ़ के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास का बजट नहीं- नागेंद्र गुप्ता



जांजगीर चांपा // समय दर्शन // छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जिला कांग्रेस कमिटी के प्रवक्ता नागेंद्र गुप्ता ने कहा कि यह बजट राज्य के संतुलित एवं सर्वांगीण विकास की भावना को प्रतिबिंबित नहीं करता। बजट में बस्तर एवं सरगुजा अंचल पर अत्यधिक फोकस किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों की चोर उपेक्षा की गई है। शासकीय रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस योजना सामने नहीं आई है। प्रोफेसर, शिक्षक-शिक्षिकाओं, डॉक्टरों सहित अन्य शासकीय पदों पर भर्ती को लेकर बजट पूरी तरह मौन है जांजगीर-चांपा जिले के लिए बजट में कोई विशेष योजना शामिल नहीं की गई है। धान उत्पादक क्षेत्र होने के बावजूद धान एवं चावल आधारित फूड प्रोसेसिंग उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया। इसी प्रकार 'सिल्क सिटी' के रूप में पहचाने जाने वाले जिले में कोसा कपड़ा बुनकरों के लिए भी कोई योजना नहीं लाई गई है। इसके साथ ही नगरीय निकायों के विकास, आधारभूत संरचना एवं जन सुविधाओं के लिए भी बजट में कोई ठोस प्रावधान नहीं है। कुल मिलाकर यह बजट न तो रोजगारोन्मुख है व्यक्ति मुक्त रोजगार और न ही छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की दिशा में संतुलित प्रयास करता है

आगामी जनगणना 2027: दो दिवसीय प्रशिक्षण हुआ संपन्न



जांजगीर-चांपा // समय दर्शन // आगामी जनगणना 2027 के अंतर्गत प्रथम चरण (मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना) के सफल संचालन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दो दिवसीय प्रशिक्षण का जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि प्रथम चरण में हाउस लिस्टिंग के अंतर्गत प्रत्येक मकान का सूचीकरण किया जाएगा। द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय जानकारी एकत्र किया जाएगा। प्रशिक्षण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि वे निर्धारित प्रपत्रों के अनुसार सावधानीपूर्वक एवं त्रुटिरहित जानकारी संकलित करें, ताकि जनगणना कार्य सफलतापूर्वक एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर द्वारा एचएलबी क्रिएटर और लेआउट मानचित्र तैयारी के माध्यम से मकानसूचीकरण ब्लॉक का नक्शा तैयार करना, सीएमएमएस में डैशबोर्ड का उपयोग, सीएमएमएस- प्रशिक्षण प्रबंधन नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड तैयार करना, आईडी कार्ड जारी करने, लॉजिस्टिक्स और प्रिंटिंग और डेटा एंट्री मॉड्यूल में क्या करें और क्या ना करें की जानकारी, ग्राम, नगर, चार्ज रजिस्ट्रारों की तैयारी डेटा नैतिकता, गोपनीयता, सुरक्षा और मोबाइल और वेब ऐप से जुड़ी समस्याओं का निवारण-ऐप के उपयोग के लिए क्या करें और क्या ना करें व डेटा सुरक्षा की जानकारी, स्वगणना प्रक्रिया और डेमो और उत्तरदाता प्राणिक और पर्यवेक्षकों की भूमिका की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला जनगणना अधिकारी श्री संदीप ठाकुर, अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, तहसील जनगणना चार्ज अधिकारी, नगरीय जनगणना चार्ज अधिकारी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

किसान-युवा उर्ध्व, सिर्फ घोषणाओं का बजट: अशोक साहू



पाटन। पूर्व उपाध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग एवं विधायक प्रतिनिधि अशोक साहू ने वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि यह बजट आम जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। उन्होंने कहा कि बजट में किसानों, युवाओं, महिलाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस एवं प्रभावी प्रावधानों का अभाव दिखाई देता है। बड़ी-बड़ी घोषणाएं जरूर की गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर राहत देने वाली योजनाओं का स्पष्ट खाका नजर नहीं आता। अशोक साहू ने धान खरीदी, रोजगार सृजन और ग्रामीण अधोसंरचना के मुद्दे पर सरकार को धेरते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और युवाओं को रोजगार देने के लिए ठोस नीति की आवश्यकता है। केवल आउटरी और शब्दों से प्रदेश का विकास संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को राहत, समर्थन मूल्य, रोजगार के अवसर और महंगाई से निजात की उम्मीद थी, लेकिन बजट में इन मुद्दों पर ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया।

कमला कॉलेज में आयोजित हुआ 4 दिवसीय स्टूडेंट स्कीलिंग प्रोग्राम

राजनांदगांव (समय दर्शन)। शासकीय कमलादेवी राठी महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव में 10 से 13 फरवरी 2026 तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और छत्तीसगढ़ सरकार के सहयोग से स्टूडेंट स्कीलिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम बैंकिंग फयनेंसियल सर्विस एंड इंश्योरेंस (बीएफएसआई) क्षेत्र में छात्राओं को कौशल प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से आयोजित हुआ था। महाविद्यालय की 86 छात्राओं ने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया और अपने कौशल को निखारा। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य डॉ. ओंकार लाल श्रीवास्तव, डॉ. जयसिंग साहू, डॉ. निवेदिता ए. लाल, श्रीमती नीलम राम धनसाय और प्रशिक्षक हरीश पाल द्वारा सरस्वती माता के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान डॉ. ओंकार लाल श्रीवास्तव ने छात्राओं को बचत और निवेश के महत्व के बारे में जागरूक किया। कार्यक्रम के पहले दिन बैंकिंग कार्य प्रणाली, बीएफएसआई और केवाईसी के बारे में जानकारी दी गई। दूसरे दिन म्यूचुअल फंड्स के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। तीसरे दिन स्टॉक मार्केट और



ट्रेडिंग की प्रक्रिया पर प्रशिक्षण दिया गया, जबकि चौथे दिन इनकम टैक्स और जीएसटी से संबंधित जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के बाद टैलेंट स्किल वासिंटी द्वारा परीक्षा आयोजित की गई और उत्तीर्ण छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. अंजली अर्वाधिया ने छात्राओं को बीएफएसआई क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं पर प्रकाश डाला और उन्हें उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। इस कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा डॉ. युगेश्वरी साहू, नोडल अधिकारी के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर डॉ. रोहित वर्मा, तुमेश्वर साहू, रेवतीरमन साहू, गोविंद कुमार, धनेश पटेल सहित अन्य शिक्षकगण और छात्राओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके परिणामस्वरूप यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। महाविद्यालय का यह प्रयास छात्रों की वित्तीय क्षमता को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, और उनकी भविष्य की संभावनाओं को उज्ज्वल बनाता है।

कर्मचारी और उसके परिवार के लिए वरदान साबित होगा कैशलेस इलाज

भूतपूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष ने शिक्षक प्रतिनिधि मंडल को दिया था कैशलेस इलाज का भरोसा

दुर्ग/रायपुर। 2026 में छत्तीसगढ़ राज्य के बजट सत्र के दौरान कैशलेस इलाज की घोषणा होने से प्रदेश के लगभग 4.5 लाख कर्मचारी और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। कर्मचारियों के विभिन्न संगठन निरंतर इसके लिए पिछले दो वर्षों से प्रयासरत थे। प्रयासों के इसी क्रम में शिक्षक एवं कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने विगत 5 जुलाई 2024 को ओम प्रकाश पाण्डेय एवं कमल वैष्णव के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के भूतपूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह जी से मुलाकात कर इस संबंध में विस्तृत चर्चा की थी और कर्मचारियों को होने वाली समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था। प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें यह भी बताया था कि कैशलेस इलाज से शासन पर भी कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा, क्योंकि कर्मचारियों



के द्वारा इलाज पर किया गया खर्च पहले भी शासन चिकित्सा प्रतिपूर्ति के रूप में कर्मचारियों को भुगतान करता रहा है। लेकिन कैशलेस इलाज योजना से कर्मचारियों को इलाज कराने के समय तात्कालिक रूप से धनराशि जमा करने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। डॉ. रमन सिंह ने कर्मचारी प्रतिनिधियों से किया गया अपना वादा आज छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के दौरान कैशलेस इलाज की घोषणा के साथ पूरा किया है इससे कर्मचारी जगत में खुशी का माहौल निर्मित हुआ है। अमितेश तिवारी, सुनील स्वर्णकार, नारायण दास जोशी, राहुल झा, बी. प्रकाश, कौशल साहू, लिखन लाल भुआर्य, काशीनाथ सिंह, पवन सिंह, राहू है। लेकिन कैशलेस इलाज योजना से कर्मचारियों को इलाज कराने के समय तात्कालिक रूप से धनराशि जमा करने की परेशानी से निजात मिल जाएगी। डॉ. रमन सिंह ने कर्मचारी प्रतिनिधियों से किया गया अपना वादा आज छत्तीसगढ़ के बजट सत्र के दौरान कैशलेस इलाज की घोषणा के साथ पूरा किया है इससे कर्मचारी जगत में खुशी का माहौल निर्मित हुआ है। अमितेश तिवारी, सुनील स्वर्णकार,

श्री परशुराम युवा वाहिनी बसना के अध्यक्ष बने भूपेन्द्र शर्मा, सचिव सुजीत दास

बसना (समय दर्शन)। बसना स्थित हरि लक्ष्मी विप्र भवन में श्री परशुराम युवा वाहिनी का गठन किया गया। उपस्थित ब्राह्मण बन्धुओं एवं श्री परशुराम वाहिनी के सदस्यों द्वारा एवं सर्व सम्मति से परशुराम युवा वाहिनी विकास खण्ड बसना का अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष चंदन मिश्रा, दीपक शर्मा, हेमसागर दास, सचिव सुजीत दास, सह सहायक सचिव विनय सतपथी, कोषाध्यक्ष हेमसागर देवता, मिडिया प्रभारी राजन कर मनोनीत किये गये।



इस बैठक में ब्राह्मण समाज कार्यकारी जिलाध्यक्ष बलदेव मिश्रा, ब्राह्मण नवयुवक संघ बसना से अध्यक्ष हेमंत दास, सचिव ललित मिश्रा, कोषाध्यक्ष छविमन्नु सडंगी, पूर्व अध्यक्ष वृंदावन सतपथी, आनंद कुमार दास, अयोध्या प्रसाद मिश्रा, राधाकांत कर, सतीश पाटी, अभिषेक दास, सौरभ कर, निलय कर, महेश पति, प्रशांत देवता एवं अन्य नवयुवक विप्र बंधु उपस्थित थे। समिति गठन के पश्चात श्री परशुराम युवा वाहिनी के नवनिर्वाहक पदाधिकारी गणों का स्वागत तिलक लगाकर नीरज दास द्वारा शुभ मंगल कामनाओं के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार शर्मा एवं सचिव सुजीत दास ने बताया कि, पूरे

बजट 2026-27 गांव से शहर तक विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखेगा - जितेन्द्र वर्मा

दुर्ग। राज्य बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत बजट 2026-27 छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है।



600 करोड़, लोकनिर्माण विभाग में 9,450 करोड़, मुख्यमंत्री आदर्श शहर योजना समृद्धि योजना 200 करोड़, महतारी वंदन योजना 8200 करोड़, मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना 6500 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 4000 करोड़, शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना में 1500 करोड़, समग्र शिक्षा अभियान हेतु 1500 करोड़, विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए 4000 करोड़ के प्रावधान सहित छत्तीसगढ़ राज्य के सभी वर्गों व क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। यह बजट छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि यह बजट विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के संकल्प को पूर्ण करने की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है।

भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का "SANKALP" बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बस्तर से लेकर सरगुजा तक सौगातों की झड़ी लगा दी है। बजट में प्रत्येक समाज के साथ-साथ युवाओं से लेकर महिलाओं-बच्चों का ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1725 करोड़, जल जीवन मिशन 3000 करोड़,

कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने जनदर्शन में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से पहुंचे आवेदकों की सुनी मांग एवं समस्याएं

जनदर्शन में आज कुल 74 आवेदन हुए प्राप्त

जांजगीर-चांपा // समय दर्शन // कलेक्टर श्री जन्मेजय महोबे ने मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन के माध्यम से जिले के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याओं, शिकायतों और मांगों को संवेदनशीलता से सुना। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों का समयबद्ध और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जनदर्शन में आज 74 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में तहसील बलौदा अंतर्गत ग्राम जर्वे ब निवासी श्रीमती रूखमणी द्वारा राजस्व प्रकरण में त्रुटि सुधार करवाने, श्री नरेन्द्र कुमार द्वारा मुर्गी पालन करने हेतु ऋण दिलवाने, तहसील पामगढ़ के ग्राम



मेऊ निवासी श्री रामेश्वर खांडे द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने, तहसील जांजगीर अंतर्गत ग्राम बसंतपुर निवासी श्री विसाहू राम साहू द्वारा मुआवजा राशि दिलाने, तहसील शिवरीनारायण अंतर्गत ग्राम कचंदा निवासी श्रीमती सुमन साहू द्वारा नया राशनकार्ड बनवाने, श्री बटालू राम रात्रे द्वारा प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि योजना का लाभ दिलाने, तहसील अकलतरा के ग्राम बिरकोनी निवासी श्री ललित सिंह द्वारा किसान किताब बनवाने एवं ऑनलाइन नाम दर्ज करवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्राचार्य सम्मेलन राजधानी में संपन्न

रायपुर (समय दर्शन)। श्री श्री विश्वविद्यालय ने राजधानी में संकल्प-2047 शीर्षक से प्राचार्य सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जिसमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य एवं शिक्षकों ने सहभागिता की। यह सम्मेलन सार्थक संवाद और सहयोग के उद्देश्य से आयोजित किया गया। मूल्य-समृद्ध समाज के निर्माण की परिकल्पना प्रतिभागियों ने शिक्षकों के कल्याण को सुदृढ़ करने के इस संरचित दृष्टिकोण को सराहना की, जिसे विद्यार्थियों के बेहतर परिणामों से जोड़ा गया। सभा को संबोधित करते हुए श्री श्री विश्वविद्यालय के कार्मिक निदेशिका स्वामी सत्यचैतन्यने शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ मूल्यों के समावेशन की आवश्यकता पर बल दिया और शिक्षा के माध्यम से शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को गहरे मानवीय स्तर पर सशक्त बनाकर तनाव-मुक्त एवं मूल्य-समृद्ध समाज के निर्माण की परिकल्पना को दोहराया।



शिक्षाविदों का मंथन: समावेशी और मानवीय शिक्षा व्यवस्था का संकल्प- सम्मेलन के प्रतिभागी शिक्षकों ने अपने-अपने संस्थानों में व्यावहारिक रणनीतियों को लागू कर संकल्प-2047 के दृष्टिकोण-एक प्रगतिशील, समावेशी और मूल्य-आधारित शैक्षिक पारिस्थितिकी तंत्र को साकार करने का प्रण लिया। विश्वविद्यालय के नेतृत्व टिम से कुलाध्यक्षा प्रो. राजिता कुलकर्णी, कुलपति प्रो. डॉ. तेज प्रताप, कार्मिक निदेशिका स्वामी सत्य चैतन्य, कार्यकारी कुलसचिव प्रो. डॉ. अनिल कुमार शर्मा तथा मानव संसाधन उपनिदेशक श्री ज्योति रंजन गडनायक प्रमुख कार्यक्रम की सफलतापूर्वक संपन्नता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए आयोजन दल के प्रयासों की सराहना कार्यक्रम की सुचारु व्यवस्था और सफलता जनसंपर्क एवं प्रवेश विभागों के संयुक्त प्रयासों से संभव हुई, जिसमें मीडिया संचार प्रबंधक हितांशु शेखर मोहंता ने संकल्प-2047 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मीडिया समन्वय एवं संचार रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग अपेक्स सदस्य सुधाकर राव, जिला शिक्षक समन्वयक महेन्द्र गुप्ता, जून शिक्षक समन्वयक नीति मिश्रा एवं आर्ट ऑफ लिविंग राज्य मीडिया समन्वयक दीपेन्द्र दीवान की महत्त्वपूर्ण और सक्रिय भागिदारी रही।

उच्च शिक्षा में सकल नामांकन- प्रबंधन अध्ययन संकाय के संकायाध्यक्ष प्रो. डॉ. विप्लव कुमार बिस्वाल ने कहा कि शिक्षा प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि सहयोग का माध्यम है, और भारत विश्व के भविष्य को आकार देने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। उन्होंने उभरते करियर पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन के परिवर्तनकारी प्रभाव पर भी चर्चा

की तथा वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (लक्ष्य) को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के राष्ट्रीय लक्ष्य का उल्लेख किया। युवा पीढ़ी में अंतर्ज्ञान और चेतना के विकास हेतु एक सार्थक पहल - विश्वविद्यालय के आईसीटी प्रमुख जयेश दौलतजादा ने स्ट्रेस टू स्ट्रेंथ विषय पर बोलते हुए व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक जीवन में तनाव

प्रबंधन के लिए दैनिक दिनचर्या में सरल श्वास तकनीकों को अपनाने की वकालत की। आर्ट ऑफ लिविंग की संकाय सदस्य पूजा जिंदल ने 'इंट्यूशन प्रोसेस' को युवा पीढ़ी में अंतर्ज्ञान और चेतना के विकास हेतु एक सार्थक पहल बताया, जो उनकी एकाग्रता, प्रतिभा और बौद्धिक विकास को सुदृढ़ करता है।

खेल से सुदृढ़ होता है राष्ट्र निर्माण - उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा

चौदहवीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया शुभारंभ

रायपुर। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल, भिलाई में चौदहवीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025-26 का सोमवार को विधिवत शुभारंभ उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल और संस्कृति का सुंदर संगम देखने को मिला।

यह राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता 24 से 27 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में देशभर की पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 30 टीमों भाग ले रही हैं, जिनमें लगभग 450 खिलाड़ी शामिल हैं। विशेष बात यह है कि 10 रात्यों के 30 से अधिक ओलंपिक, वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स और साउथ एशियन गेम्स जैसी प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। जिसमें अर्जुन पुरस्कार विजेता असम के डीएसपी श्री जनता तालुकार एवं राजस्थान के डीएसपी श्री रजत चौहान भी प्रतियोगी के रूप में शामिल हुए।



अपने संबोधन में उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि पुलिस बल केवल कानून - व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल और अनुशासन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि अखिल

भारतीय स्तर की इस प्रतियोगिता से पुलिस बलों के बीच समन्वय, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ को इसकी मेजबानी नहीं है, बल्कि खेल और अनुशासन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि अखिल

भारतीय स्तर की इस प्रतियोगिता से पुलिस बलों के बीच समन्वय, नेतृत्व क्षमता और टीम भावना को मजबूती मिलेगी। छत्तीसगढ़ को इसकी मेजबानी नहीं है, बल्कि खेल और अनुशासन के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। उन्होंने कहा कि अखिल

श्रीमती अलका बाघमार, पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम, एडीजी श्री एस.आर.पी. कल्लूरी, एडीजी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल श्री विवेकानंद सिन्हा, आईजी श्री ओ.पी. पाल, आईजी श्री अजय यादव, आईजी श्री अभिषेक शांडिल्य, आईजी श्री बी.एस. ध्रुव, डीआईजी श्री कमलेश्वर कश्यप, डीआईजी श्री एम.आ. आहिर, डीआईजी मध्य रेंज एवं आयोजन सचिव श्री सदानंद कुमार, डीआईजी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्गा श्री विजय अग्रवाल, कलेक्टर श्री अर्जुन सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री राठौर तथा प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के डीआईजी कमांडेंट एवं पुलिस खेल अधिकारी श्री राजेश कुकरेजा सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इसके साथ ही पद्मश्री सम्मानित समसाद बेगम, श्री भारती बंधू, श्री आलोक निरंजन एवं पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुन भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहीं।

06 असामाजिक तत्व जेल निरूद्ध, 05 माह से फरार 02 आरोपी गिरफ्तार



रायपुर। पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) श्रीमती श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संदीप मिश्र के नेतृत्व में आगामी होली पर्व के मद्देनजर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना तिल्दा-नेवरा, थाना धरसीवा एवं थाना विधानसभा पुलिस द्वारा लगातार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

परिशांति भंग करने वाले 06 असामाजिक तत्व जेल निरूद्ध

थाना तिल्दा-नेवरा क्षेत्र के मोहनपुरा पारा नेवरा, पुरानी बस्ती तिल्दा, सासाहोली एवं ग्राम टंडवा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जबरन विवाद एवं मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और संबंधित व्यक्तियों को समझाने का प्रयास किया गया, किंतु वे उग्र होकर शांति भंग करने एवं मारपीट पर उतारू हो गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुल 06 आरोपियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल निरूद्ध किया गया। थाना तिल्दा-नेवरा के अपराध क्रमांक 554/2026, धारा 333, 296,

50 किलोग्राम गांजा व नगदी रकम के साथ गांजा की तस्करी मामले में 01 अन्य आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर किया गया आरोपी राजकिशोर बेहरा उर्फ मिलन को उड़ीसा से गिरफ्तार। आरोपी द्वारा पैडलर के रूप में कार्य कर अपने खाते में रुपये लेकर मादक पदार्थ दिलाने का करता था काम। आरोपी के कब्जे से 02 नग मोबाइल किया गया है जिस में 02 आरोपी को किया जा चुका है गिरफ्तार। थाना सिविल लाईन पुलिस एवं फ्राईम टीम द्वारा की गई कार्यवाही। आरोपियों के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 88/2026 धारा 20(सी), 29 नारकोटिक एक्ट के तहत की गई है कार्यवाही। विवरण:- दिनांक 14.02.2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ था कि थाना सिविल लाइन क्षेत्रांतगत केनाल रोड स्थित दुर्गा मंच के पीछे खाली मैदान में एक चारपहिया वाहन में सवार दो व्यक्ति अवैध रूप से गांजा रखकर बिक्री के उद्देश्य से ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। जिस पर उक्त



स्थान में रेड कार्यवाही कर आरोपी हृषिकेश उर्फ ऋषिकेश उर्फ ऋषि सरोज एवं हिमांशु दामले को पकड़कर उनके कब्जे से 50 किलोग्राम गांजा एवं नगदी रकम 02 लाख रुपये जब्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया था। प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों से

पुछताछ तथा फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर अन्य संलिप्त आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। इसी क्रम में प्रकरण में संलिप्त पैडलर राजकिशोर बेहरा उर्फ मिलन के संबंध में इनपुट प्राप्त हुआ। जिस पर आरोपी राजकिशोर बेहरा उर्फ मिलन को उड़ीसा से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 02 नग मोबाइल फोन जब्त कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है।

एचडीएफसी बैंक ने गुवाहाटी में नई टेक और डिजिटल फैक्ट्री का शुभारंभ किया

गुवाहाटी: भारत के निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंक, एचडीएफसी बैंक ने आज गुवाहाटी में अपनी नई टेक और डिजिटल फैक्ट्री का शुभारंभ किया। यह सुविधा असम में एडवांस्ड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इनोवेशन और टैलेंट इनक्यूबेशन के लिए एक सेंटर के तौर पर काम करेगी, जिससे स्टार्ट-अप और डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी टैलेंट पूल को मजबूत करने में मदद मिलेगी। यह सुविधा बैंक की असम में पहली और देश भर में चौथी है। बैंक की अभी मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम में टेक और डिजिटल फैक्ट्रियां हैं।

इस सुविधा का उद्घाटन असम के माननीय मुख्यमंत्री, डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने एचडीएफसी बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कैजाद भरुचा, बैंक के चीफ इन्फ्रामेंशन ऑफिसर श्री रमेश लक्ष्मीनारायण असम सरकार के गणमान्य लोगों और एचडीएफसी बैंक के अन्य अधिकारियों की

मौजूदगी में किया। यह सुविधा राज्य में स्किल्ड प्रोफेशनल्स को करियर के मौके भी देगी, जिससे वे अगली पीढ़ी को टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में सीधे योगदान दे सकेंगे। बैंक असम और आस-पास के राज्यों से लोकल टेक टैलेंट का फ़ायदा उठाकर टेक और डिजिटल फैक्ट्री के लिए अपनी क्षमताओं को मजबूत करेगा। इसका मकसद एआई, क्लाउड, डेटा और कोर इंजीनियरिंग ट्रेक में कोर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है, ताकि स्टार्ट-अप डिजिटल प्रोडक्ट बनाने की क्षमता को खोला जा सके।

एचडीएफसी बैंक ने असम के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एडवांटेज असम 2.0 के हिस्से के तौर पर असम सरकार के साथ पार्टनरशिप की है। इस सांझी पहल के तहत एचडीएफसी बैंक और असम सरकार बीएफएसआई और फ़िन्टेक सेक्टर से जुड़े एक स्ट्रुक्चर्ड स्किल-बिल्डिंग करिकुलम के ज़रिए इंडस्ट्री एक्सपर्टों के साथ एकेडमिक

नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं। कैंपस-टू-कॉर्पोरेट कॉम्पिटेंसी पर केंद्रित, यह प्रोग्राम बैंकिंग और फ़िन्टेक इंडस्ट्री में नौकरी की ज़रूरतों के हिसाब से है। करिकुलम में ज़रूरी बैंकिंग नॉलेज और नए ज़माने के आईटी डोमेन शामिल हैं।

यह प्रोग्राम सितंबर 2025 में शुरू हुआ था और अभी 150 से ज्यादा स्टूडेंट्स को प्रोग्राम के रूप के हिस्से के तौर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। स्टूडेंट्स को एचडीएफसी बैंक के सीनियर एग्जीक्यूटिव से इंडस्ट्री से जुड़ी नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलेगा। जो स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, उन्हें एचडीएफसी बैंक के साथ 2 - 4 महीने की इंटरनैशियनल करनी होगी, जिससे उन्हें कॉर्पोरेट माहौल में असल दुनिया के हालातों में एकेडमिक और टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट को लागू करने का एक्सपीरियंस मिलेगा। इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा।

टूज़ोन सोलर ने छत्तीसगढ़ के बाजार में रखा कदम, भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन के प्रति अपने संकल्प को किया मजबूत

रायपुर: भारत के अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कंपनी 'सनटेक एनर्जी सिस्टम्स' के प्रमुख ब्रांड 'टूज़ोन सोलर' (Truzon Solar) ने छत्तीसगढ़ के लिए 'मेटालोन इंडिया' को अपना 'एक्सक्लूसिव मास्टर डीलर' नियुक्त करने की घोषणा की है। इस साझेदारी के साथ टूज़ोन सोलर ने आधिकारिक तौर पर छत्तीसगढ़ के बाजार में प्रवेश कर लिया है। इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य राज्य में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और भारत के तेजी से बढ़ते सौर ऊर्जा बाजारों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना है।

इस ऐतिहासिक अवसर पर सीएसपीडीसीएल के कार्यकारी निदेशक श्री एस. के. गजपाल, टूज़ोन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री भवानी सुरेश, टूज़ोन सोलर के सीईओ श्री जकुला श्रीनिवास और मेटालोन इंडिया की संस्थापक सुश्री सस्मिता कर



उपस्थित थी। उनकी सामूहिक उपस्थिति प्रगतिशील शहरी शासन और शाश्वत ऊर्जा समाधानों के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाती है, जो भविष्य के शहरों के

निर्माण में स्वच्छ ऊर्जा के महत्व पर जोर देती है। कंपनी द्वारा उठाए गए इस रणनीतिक कदम के महत्व को रेखांकित

करते हुए टूज़ोन सोलर के संस्थापक और प्रबंध निदेशक भवानी सुरेश ने कहा, 'छत्तीसगढ़ में मेटालोन के साथ यह साझेदारी केवल व्यावसायिक विस्तार तक सीमित नहीं है; बल्कि यह छत्तीसगढ़ में एक लचीली और भविष्योन्मुखी अक्षय ऊर्जा आधारित पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह विस्तार केवल दायरे को बढ़ाने के बारे में नहीं है, बल्कि संबंधित पक्षों के साथ जमीनी स्तर पर काम करते हुए निरंतर मूल्य प्रदान करने के लिए एक उचित कार्यप्रणाली स्थापित करने के बारे में है।'

टूज़ोन सोलर के सीईओ जकुला श्रीनिवास ने कहा, हमने सौर ऊर्जा के विकास में हमेशा अपार संभावनाएं देखी हैं। मेटालोन इंडिया के साथ हमारी साझेदारी कार्यान्वयन में उत्कृष्टता और दीर्घकालिक मूल्य निर्माण के हमारे

साझा दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसमें हमारे इंजीनियरिंग कौशल और क्षेत्रीय मजबूती का मेल है। साथ ही, हम एक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले सौर बुनियादी ढांचे की नींव रख रहे हैं, जो भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को मजबूती देगा और शाश्वत आर्थिक विकास में योगदान देगा। टूज़ोन सोलर को छत्तीसगढ़ में बाजार की मजबूत वृद्धि की उम्मीद है। कंपनी का लक्ष्य अपने मुख्य वितरक के माध्यम से बिक्री और सेवा में भारी वृद्धि करना है। आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों में सौर ऊर्जा की बढ़ती मांग को देखते हुए, कंपनी की वर्तमान 205 मेगावॉट की स्थापित क्षमता को 2028 तक दोगुना करने की योजना है। छत्तीसगढ़ के बाद, कंपनी ने आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश, ओडिशा और केरल जैसे राज्यों में विस्तार की रणनीति बनाई है।

संक्षिप्त समाचार

Galaxy AI ने मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम का किया विस्तार; यूजर्स को मिलेंगे अधिक विकल्प और बेहतर नियंत्रण

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने आज अपने गैलेक्सी इकोसिस्टम में गैलेक्सी AI का विस्तार करते हुए मल्टी-एजेंट इकोसिस्टम को और मजबूत करने की घोषणा की है। कंपनी का उद्देश्य यूजर्स को अधिक विकल्प, और बेहतर नियंत्रण देना है, ताकि वे अपने दैनिक कार्य कम मेहनत और अधिक स्वाभाविक तरीके से पूरे कर सकें।

कंपनी के अनुसार, अब लोग अलग-अलग कामों के लिए कई तरह के AI एजेंट्स का उपयोग कर रहे हैं। हालिया आंकड़ों के मुताबिक, 10 में से लगभग 8 यूजर्स दो या उससे अधिक AI एजेंट्स पर निर्भर हैं। इसी बदलाव को देखते हुए, सैमसंग गैलेक्सी AI को इस तरह विकसित कर रहा है कि यूजर अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से अलग-अलग इंटीग्रेटेड एआई अनुभवों को चुन सकें। गैलेक्सी AI को ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम के स्तर पर गहराई से जोड़ा गया है। यह केवल किसी एक ऐप तक सीमित रहने के बजाय पूरे डिवाइस के सिस्टम लेवल पर काम करता है। यह यूजर की जरूरतों को समझते हुए ज्यादा स्वाभाविक और सरल इंटरैक्शन सुनिश्चित करता है।

इससे बार-बार ऐप बदलने या एक ही कमांड को बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती और एआई बैकग्राउंड में बिना किसी रुकावट के काम करता रहता है। साथ ही, सैमसंग अपने अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए परफॉर्मिंस जैसी सहायक सेवाओं को भी जोड़ रहा है, ताकि पूरा गैलेक्सी इकोसिस्टम एक जैसा और सहज महसूस हो। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के मोबाइल एक्सपीरियंस (MX) बिजनेस के प्रेसिडेंट और आर एंड डी हेड, वॉन-जून चोई ने कहा, हम एक खुले और समावेशी एआई इकोसिस्टम के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो यूजर्स को जटिल कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए अधिक विकल्प और

एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने RuPay ऑन-द-गो कार्ड्स के लिए इंस्टैंट NFC-बेस्ड बैलेंस अपडेट लॉन्च किया

आज एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपने RuPay NCMC ऑन-द-गो कार्ड्स पर इंस्टैंट हल्ड बैलेंस अपडेट फीचर पेश किया। अब ग्राहक अपने कार्ड का बैलेंस हल्ड फॉवर्ड एन्डॉयड स्मार्टफोन पर कार्डकोटैप करके तुरंत चेक और अपडेट कर सकते हैं, जिससे मेट्रो स्टेशन के कियोस्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्सप्रेस हो, पूरी तरह से डिजिटल यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। यह फीचर एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने कुछ महीने पहले पेश करके इसके वास्तविक उपयोग की जानकारी एकत्रित की थी तथा ग्राहकों का फीडबैक लिया था। इस पायलट में ग्राहकों ने इसे बहुत पसंद किया तथा इसे काफ़ी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। इससे साबित हो गया कि यह फीचर यूजर्स के लिए काफ़ी दैनिक उपयोगिता रखता है। यूजर्स का पॉजिटिव फीडबैक मिलने के बाद अब बैंक इसे अपने RuPay ऑन-द-गो कार्ड्स के सभी यूजर्स के लिए लॉन्च कर रहा है। इससुविधकेसाथ, यात्री एयरटेल बैंक ऐप पर अपने बैंक खाते या वॉलेट में लॉगइन करने के बाद, अपनेलिककिएएए NFC-इनेबल्ड एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर कार्ड टैप करके अपने कार्ड बैलेंस को रियल टाइम में अपडेट या चेक कर सकते हैं। कार्ड ऑर्डर करने और रिचार्ज करने से लेकर बैलेंस को तुरंत अपडेट या चेक करने तक, पूरी प्रक्रिया अब पूरी तरह से डिजिटल, बिना कतार के और बेहद आसान है।

एयरटेल ने बड़े पैमाने पर डिजिटल एनबीएफसी प्लेटफॉर्म स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की

नई दिल्ली: भारत की अग्रणी टेलीकम्यूनिकेशंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों में से एक भारतीय एयरटेल ने आज अपनी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) इकाई एयरटेल मनी लिमिटेड के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की। यह कदम भारत में ऋण उपलब्धता की कमी को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एनबीएफसी सहायक कंपनी को आने वाले कुछ वर्षों में कुल 20,000 करोड़ रुपये की पूंजी से सशक्त किया जाएगा। इसमें एयरटेल 70 प्रतिशत निवेश करेगी, जबकि शेष 30 प्रतिशत राशि प्रमोटर समूह के माध्यम से भारतीय एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा निवेश की जाएगी।

एयरटेल के पास मजबूत डिजिटल संपत्तियां, 500 से अधिक डेटा वैज्ञानिकों द्वारा संचालित बड़े डेटा और एनालिटिक्स इंजन तथा व्यापक संचालन अनुभव है। इन्होंने क्षमताओं के आधार पर एयरटेल पूरे देश में आसान, सुरक्षित और नई तरह की डिजिटल वित्तीय सेवाएं तेजी से लोगों तक पहुंचाना चाहती है।

पिछले दो वर्षों में एयरटेल ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और एकीकृत चैनलों के आधार पर एक उच्च क्षमता वाला क्रेडिट इंजन विकसित किया है, जिसके परिणामस्वरूप देश के सबसे मजबूत लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर (एलएसपी) मॉडल में से एक तैयार हुआ है।

यह प्लेटफॉर्म पहले ही बड़े स्तर पर अपनाया जा चुका है और अब तक 9,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण वितरित कर चुका है। सख्त जांच प्रक्रिया, संतुलित लोन प्रबंधन और रियल टाइम जोखिम निगरानी की वजह से लोन न चुकाने के मामले बेहद कम रहे हैं और उद्योग के सर्वोत्तम मानकों के अनुरूप नियंत्रित रहे हैं। भारतीय एयरटेल के एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन गोपाल विट्टल ने कहा, पिछले दो वर्षों में हमारे एलएसपी प्लेटफॉर्म की सफलता इस बात का प्रमाण है कि हम तकनीक, डेटा और ग्राहकों के भरोसे को जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालने में सक्षम हैं। हमने देश के सबसे भरोसेमंद और विस्तार योग्य डिजिटल क्रेडिट इंजनों में से एक तैयार किया है, जो लाखों लोगों तक उच्च गुणवत्ता वाला ऋण पहुंचा रहा है और यह उद्योग के उच्च मानकों को खरा उतरा है। हमारा एनबीएफसी विस्तार इस मजबूत नींव को और मजबूत करेगा। यह दिखाता है कि हम एक अलग पहचान वाला और भविष्य के लिए तैयार डिजिटल लोन कारोबार बनाना चाहते हैं, जो भरोसे, नई सोच और ज्यादा लोगों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने पर आधारित होगा। एयरटेल मनी को 13 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ। भारत के तेजी से बढ़ते वित्तीय सेवा क्षेत्र में यह विस्तार इस बात का प्रमाण है कि एयरटेल अधिक से अधिक लोगों तक औपचारिक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने और अब तक वंचित रह गए ग्राहकों को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

वीडियो खेल बच्चों को बना रहे हैं आतंकी

संपादकीय



कांग्रेस को सबक लेना चाहिए

कांग्रेस की मुश्किल यह है कि समर्थन आधार बढ़ाने की कोई कार्ययोजना उसके पास नहीं है। उसके नेता और कार्यकर्ता राजनीति की धूल-धक्कड़ में नहीं उतरना चाहते। वे नफ़ासत से सियासत करते हैं, जिसका भारी नुकसान जनाधार का सिकुड़ते जाना है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ सत्ता साझा करने की संभावना से दो टूक इनकार कर इंडिया एलायंस को वैसे विवाद से बचा लेने की कोशिश है, जिसका भारी नुकसान इस समूह को कई राज्यों में उठाना पड़ा। गौरतलब है कि हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश लेकर बिहार तक- ऐसे विवाद में समान पात्र कांग्रेस रही। मध्य प्रदेश और हरियाणा में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने की अपनी हैसियत को जताते हुए टिकट बंटवारे में उसने समाजवादी पार्टी या अन्य छोटे दलों की मांगों को सिरे से ठुकरा दिया। महाराष्ट्र और बिहार में अधिक सीटों पर उम्मीदवारी पाने के लिए सबसे बड़े दल पर उसने कई कोण से दबाव बनाए, जिसे बदमजग़ी पैदा हुई। दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री के चेहरे को समर्थन देने में उसने हील-हुज्जत की, जिससे गठबंधन में बिखराव का संदेश गया। अब वही तरीका तमिलनाडु की कांग्रेस इकाई ने कुछ समय पहले से अपनाया हुआ था। चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीट और चुनाव के बाद अगर सत्ता मिली, तो सरकार में मंत्री पद का पहले से वादा- कांग्रेस को इन दो मांगों से गठबंधन के अंदर खींचतान का माहौल बन रहा था। डीएमके ने दोनों मांगों को ठुकरा दिया है। इस तरह अब यह कांग्रेस पर है कि वह राज्य में फिलहाल सत्ताधारी गठबंधन में रहे या नहीं। लोकतंत्र में सत्ता में आने की अपेक्षा रखना उचित ही है। लेकिन सत्ता मिलना या ना मिलना समर्थन आधार की ताकत से तय होती है। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि समर्थन आधार बढ़ाने की कोई कार्ययोजना उसके पास नहीं है। संभवतः कांग्रेस नेतृत्व को इसकी चिंता भी नहीं है। उसके नेता और कार्यकर्ता राजनीति की धूल-धक्कड़ में नहीं उतरना चाहते। वे नफ़ासत से सियासत करते हैं, जिसका पड़नाम जनाधार का सिकुड़ते जाना है। ऐसे में अधिकांश राज्यों में सहयोगी दलों की पीट पर सवारी उनकी मजबूरी बन गई है। मगर इन्हें भी वे अपनी शर्त थोपना चाहते हैं। इसका खराब तजुर्बा सहयोगी दलों को हुआ है। मगर वैसे अनुभव से गुजरने से डीएमके ने इनकार किया है, तो कांग्रेस को उससे सबक लेना चाहिए।

ऑपरेशन भी होगा तो शर्तों के साथ

हरिशंकर व्यास

तो आज का वक़्त भारत का सेनापति बेचारा (थलसेना प्रमुख-जनरल एमएम नरवणे) 'सबसे ऊपर से'। आदेश की प्रतीक्षा के अनुभव वाला। अंत में जवाब - जो उचित समझो, वह कर। कितनी गंभीर बात। तभी विचार करिं नेहरू के बनाए भारत और जिन्ना के बनाए पाकिस्तान में क्या फर्क है? नेहरू की ज़िद थी कि सिविल सरकार से सेना आदेश लेगी। जबकि जिन्ना ने दिमाग नहीं लगाया। नतीजतन पाकिस्तान में रिवाज है सेना देगी सिविल सरकार को आदेश। जब चलाएगी सरकार।इस फर्क को क्या नरेंद्र मोदी, अजित डोवाल, राजनाथ सिंह, अमित शाह, जयशंकर या संघ परिवार के लाठीधारी जानते हैं? चलिए आज आपको राहुल गांधी के पुरखे जवाहरलाल नेहरू की सैमक का एक प्रमाण दें। वह सबूत, जिससे पाकिस्तान में लोक सर्वशाकिमना है वही लोकतांत्रिक भारत भयाकुल सिविलियन नरेंद्र मोदी से शासित है। नेहरू आजादी से पहले अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे। वायसराय की कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष थे। वह कार्यकारिणी देश के प्रशासन का बिंदु थी। उसमें ब्रितानी सेना के प्रमुख की सदस्यता अनिवार्य थी। पर नेहरू ज्योंहि उपाध्यक्ष बने उनका निर्णय था नागरिक व्यवस्था, राजनीतिक निर्णयों की बैठकों में सेना प्रमुख का क्या काम! वह सदस्य नहीं होगा। उन्होंने वायसराय कार्यकारिणी में सेना प्रमुख को सदस्य नहीं बनाने की अनुशंसा की। नेहरू ने साफ स्टैंड लिया कि शासन-प्रशासन से सेना को दूर रखा जाना चाहिए, ताकि सत्ता का संतुलन नागरिक नेतृत्व के अधीन रहे। तब नेहरू और कांग्रेस नेताओं को बोध था कि भारत में विदेशी शासन सैन्य छवनिर्णयों के बल पर था। सो, भविष्य के लोकतांत्रिक भारत में सेना को शासन से दूर रखने का निर्णय हुआ। और नेहरू ने वायसराय कार्यकारिणी में सेना प्रमुख के स्थान पर सेना के प्रतिनिधि मंत्री के रूप में नेता सरदार बलदेव सिंह को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। फिर वह हस्तक्षेप प्रयास किया, जिससे सेनाध्यक्ष की प्रशासनिक मामलों से दूरी बनी। वह हस्तक्षेप न हो और न ही नीतिगत निर्णयों में निर्णयकर्ता या भागीदार बने। लोकतंत्र को स्थिर, टिकाऊ बनाए रखने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर एक कैबिनेट समिति का गठन किया। इसी से नागरिक और सैन्य नेतृत्व के बीच एक संस्थगत संतुलन स्थापित हुआ। इसके अलावा, नेहरू ने वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के कार्यकाल को निश्चित अवधि का बनाया, जिससे सैन्य पदों पर अनानवश्यक राजनीतिक प्रभाव को रोका जा सके। सेवानिवृत्त सेना प्रमुखों, जैसे जनरल करियप्पा, को दूरस्थ देशों में राजदूत नियुक्त किया। मतलब सैन्य नेतृत्व की राजनीतिक सत्ता से दूरी बनाए रखने की परंपरा बनाई। खुफिया एजेंसियों के माध्यम से निगरानी तंत्र विकसित किया। तभी नेहरू से मोदी के सत्ता में आने तक हर सरकार ने तीनों सेनाओं के प्रमुख अलग-अलग रखे। चीन के हमले के बाद तीनों सेना के कमान से ऊपर एक प्रमुख की नियुक्ति की सलाह दी जाती रही। लेकिन भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने नेहरू की इस समझ को अपनाए रखा कि एक शक्तिशाली सैन्य पद लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। उस सोच-सावधानी के प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष का पद (चीफ ऑफ डिफेंस स्टायफ यानी सीडीएस) बना कर और सन् 2020 में जनरल रावत को नियुक्त कर खत्म किया। शायद इसलिए क्योंकि गुजरात से आए नरेंद्र मोदी ने अपनी कमी (सोधे बात करने, निर्देश देने, कैबिनेट में रियल वक्राव विमर्श निर्णय की क्षमता, विश्वास में कमी) को ढकने के लिए सीएमओ के ढर्रे पर खास-विश्वस्त एनएसए अजित डोवाल, पीएमओ के प्रमुख सचिव, विश्वस्त अमित शाह की कमांड बनाई तो सेना के लिए भी एक विश्वस्त की जरूरत थी।

प्रमोद भार्गव

अमेरिकी दैनिक न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के अनुसार माइनक्राफ्ट और रोबलॉक्स जैसे लोकप्रिय वीडियो खेल किशोर और बालकों को आतंकी बनाने का मानवता विरोधी काम कर रहे हैं। अतएव आपके लाडुले को यदि मोबाइल पर गेम खेलने की लत लग गई है तो होशियार हो जाइए, क्योंकि अब बच्चों को इन खेलों के जरिए आतंकवाद का पाठ पढ़ाए जाने का खतरनाक सिलसिला शुरू हो गया है। इन प्रशिक्षित नाबालिगों को बाद में आतंकवादी संगठनों और नफ़त फैलाने वाले समूहों में भर्ती करा दिया जाता है। जिससे ये आतंक और नफ़त फैलाने के औजार बन जाएं।इस सच्चाई को उजागर करने का काम यूनाइटेड नेशंस की काउंटर-टेरिज्म कमेटी ने किया है। इसके अनुसार यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आतंकवाद से जुड़े मामलों में अब 42 प्रतिशत आरोपी नाबालिग हैं। 2021 की तुलना में यह आंकड़ा तीन गुना अधिक है। नीदरलैंड के हेग स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर काउंटर-टेरिज्म के अनुसार यूरोप में 20 से 30 प्रतिशत आतंकवाद विरोधी गतिविधियों में हुई जांचों में 12-13 साल के बच्चे शामिल पाए गए हैं। अनेक ऑनलाइन प्लेटफ़र्म के जरिए कट्टरपंथी संगठन तेजी से किशोर और बालकों को आतंकी बनाने का खेल खेल रहे हैं। ये प्रशिक्षित बच्चे इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि भारत में आतंक फैलाने की दृष्टि से बच्चों और किशोरों को आतंकी बनाने का काम पाकिस्तानी सेना अर्से से कर रही है। मुंबई के 26/11/2008 के आतंकी हमले में शामिल अजमल कसाब इसका जीता-जागता उदाहरण रहा है। इस सच्चाई का खुलासा संयुक्त राष्ट्र भी कर चुका है। पाकिस्तान के पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल एवं पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई के सेवानिवृत्त अधिकारी रहे शाहिद अजीज ने 'द नेशनल डेली' अखबार में पहले ही यह मुद्दा उठा दिया था कि 'कारगिल की तरह हमने कोई सबक नहीं लिया है। हकीकत यह है कि हमारे गलत और ज़िद्दी कामों की कीमत हमारे बच्चे अपने खून से चुका रहे हैं। हमने इस धंधे को व्यापार का जरिया बना लिया है। वह भी



अपनी ही कौम के किशोर एवं युवाओं के जीवन को दांव पर लगाने का खेल खेलते हुए!

पूरी दुनिया में इस समय डिजिटल खेलों का कारोबार बढ़ रहा है। इस कारण दुनिया इनके निर्माण और निर्यात में दिलचस्पी ले रही है। नतीजतन इसका रूप दैत्याकार होता जा रहा है। फिलहाल विश्व में लोकप्रिय डिजिटल खेलों में मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल), फेंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफ़र्म, माइनक्राफ्ट, रोबलॉक्स, झीम-11, कोरियन लवर गेम और लुडो किंग हैं। ये सभी खेल भारत समेत लगभग सभी देशों में उपलब्ध हैं। भारत से संचालित होने वाली खेल कंपनियों में चीन सहित कई देशों की कंपनियों की पूंजी लगी हुई है। इन खेलों के अमेरिका, चीन, भारत, ब्राजील और स्पेन बड़े खिलाड़ी हैं। हाल ही में गजियाबाद में तीन सगी नाबालिग बहनों द्वारा नौवैं मॉजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया हुआ है। इन बहनों ने ऑनलाइन टास्क बेस्ट कोरियन लवर गेम खेलने की लत लग गई थी।इसी आत्मघाती खेल को खेलते हुए इन बहनों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी। इस घटना से साफ होता है कि ये खेल कितने खतरनाक है।

यकीन हो गया है कि सरेंडर नहीं किए तो मारे जाएंगे

सुनील दास

चाहे छत्तीसगढ़ के नक्सली हों या आसपास के राज्य के नक्सली हों या उनके सबसे बड़े नेता उनको अमित शाह की नक्सलियों की सफ़या नीति पर प्रभावी अमल से यकीन हो गया है कि वह सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे।यही वजह है कि पिछले एक दो साल में कई बड़े नेताओं ने सरेंडर किया ताकि वह जिंदा रहें।जिन बड़े नेताओं ने सरेंडर नहीं किया वह सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हैं। बड़े बड़े नेताओं के मारे जाने के कारण ही नक्सलियों में पहली बार मारे जाने का खौफ पैदा हुआ है। जब बड़े नेता मारे गए तो निजले स्तर के नक्सली नेताओं को एहसास हुआ कि जब बड़े नेता अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे और मारे जाने के खौफसे ही जितने नक्सली मारे गए हैं, उससे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। अमित शाह को यह बड़ी सन्तुष्टा है कि पहले किसी क्षेत्र में नक्सलियों का खौफहुआ करता था आज दो साल में स्थिति यह हो गई है कि क्षेत्र के नक्सलियों में मारे जाने का खौफहै। अमित शाह ने नक्सलियों में मारे जाने का जो खौफपैदा किया है, वह इससे पहले किसी राज्य या देश के किसी गृहमंत्री ने पैदा नहीं किया था। राज्यों के कितने ही गृहमंत्री आए गए,देश के कितने ही गृहमंत्री

आए गए लेकिन कोई नक्सलियों में मारे जाने का खौफ पैदा नहीं कर सका था।वे सब मानते ही नहीं थे कि नक्सलियों में मारे जाने का खौफपैदा किया जा सकता है।इसलिए वह ऐसा कोई तरीका सोच भी नहीं पाए। अमित शाह से तय कर लिया कि इतने समय में नक्सलियों का सफ़या करना है तो योजना बनाई कि कैसे नक्सलियों का उनके गढ़ में घुसकर मारा जा सके है। सुरक्षा बलों की संख्या को नक्सलियों से ज्यादा किया। इससे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर कर मारना शुरू किया। कई बड़े नेताओं को घेर कर मार गिराया। इससे एक ओर तो सुरक्षा बलों में भरोसा पैदा हुआ कि हम नक्सलियों का मार सकते हैं और नक्सलियों में डर पैदा हुआ कि अब उनका कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है और वह कभी भी मारे जा सकते हैं। अगर अमित शाह ने नक्सलियों में यह खौफ पैदा न किया होता कि वह सरेंडर नहीं करेंगे तो कभी भी, कहीं भी मारे जा सकते हैं, नक्सलियों की संख्या बस्तर सहित कई राज्यों में कम नही हुई होती।नक्सलियों की संख्या बस्तर में कम होने के साथ ही आसपास के राज्यों में भी कम होती गई है तो छत्तीसगढ़ सहित भाजपा शासित राज्यों में नक्सलियों के मारे जाने के कारण और सबसे ज्यादा सरेंडर करने के कारण कम हो गई है।नक्सलियों की संख्या कम

होने के कारण बड़े नेताओं के सामने भी स्थिति यह हो गई थी कि वह कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। क्योंकि कुछ करने के लिए आदमियों की जरूरत होती है। वह न पहले जैसे हमला कर पा रहे थे, न नए सदस्य भर्ती कर पा रहे थे, न कहीं ट्रेनिंग दे पा रहे थे, उनके सुरक्षित ठिकाने नष्ट कर दिए गए तो बड़े नेताओं को लगा कि जान तो उनकी अब किस राज्य में बच नहीं सकती उनके सामने भी सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। यही वजह है कि सबसे बड़े नक्सल नेता देवजी को भी सरेंडर करना पड़ा है। बसवा राजु,माडवें हिड़मा, चलपति, प्रयाग मांझी,मोडेन बालाकृष्ण,रामचंद्र रेड्डी उर्फराजू दादा,सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा, गणेश उइके,जगदीश सुधाकर आदि सरेंडर नहीं करने के कारण मारे जा चुके है,देवजी के सरेंडर करने के बाद अब माना जा रहा हैकि मिसीर बेसरा,व गणेश सहित गिनती के लोग ही बचे हैं। इससे नक्सली संगठन अब नाम को ही बचा है। जहां कहीं नक्सली गिनती के बचे हैं, वह भी सरकार को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि वह सरेंडर करना चाहते हैं। बीबीएम के बचे हुए 15 सदस्यों ने गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो वह सरेंडर करना चाहते हैं।अगर यह सरेंडर होता है तो महासमुंद जिला नक्सलमुक्त घोषित

किया जा सकता है।राजनांदागांव रेंज में महाराष्ट्र,मप्र,छत्तीसगढ़ जोन(एमएमसी जोन)के माओवाद प्रभावित जिले दिसंबर में ही नक्सलमुक्त हो गए हैं।इसमें खैरागढ़,छुईखदान,गंडई,राजनांदगांव, कबीरधाम जिला शामिल हैं। नक्सलियों के मारे जाने व सरेंडर किए जाने से उम्मीद की जा सकती है कि जहां भी नक्सली बचे हैं, उन तक बड़े नेताओं के सरेंडर करने से भय संदेश तो पहुंच रहा है कि मारे जाने से अच्छा है कि सरेंडर करना क्योंकि नक्सली संगठन बचा भी रहता है तो आज वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह कहीं कुछ कर सके क्योंकि उसके पास न पैसा है और न ही पहले जैसा संगठन। जो नक्सली नेता सरेंडर करता है तो वह यही कहता है कि बदलते सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक हालात में सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है वह अब संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं। जब अमित शाह ने नक्सलवाद के खामे की तारीख बताई थी तो बहुत कम लोगों को लगता था कि ऐसा हो पाएगा लेकिन अब जब इस तारीख को कुछ दिन बचे हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि 26 मार्च के पहले ही नक्सलवाद का खामा मोटे तौर हो जाएगा।जो अब तक असंभव माना जाता था वह अब संभव लगता है लोगों को।

पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अहम

अजीत द्विवेदी

वैसे तो अप्रैल में पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं लेकिन सबकी नजर पश्चिम बंगाल पर है। और ऐसा होने के कई कारण हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि तमिलनाडु का चुनाव कम महत्वपूर्ण है या केरल और असम का चुनाव ज्यादा महत्व का नहीं है। असम और केरल का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए एक जीवन मरण का चुनाव है तो तमिलनाडु डीएमके, अन्ना डीएमके और फिल्म स्टार विजय के लिए बहुत अहम है। परंतु राष्ट्रीय स्तर पर जिस चुनाव का सबसे ज्यादा असर होगा वह पश्चिम बंगाल का है। अगर ममता बनर्जी लगातार चौथी बार चुनाव जीतीं हैं तो सिर्फ बंगाल नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित होगी और सिर्फ भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए पर ही नहीं, बल्कि विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की राजनीति पर भी बड़ा असर होगा। चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वह अकेले सभी 294 सीटों पर लड़ेगी। दूसरी ओर वामपंथी पार्टियों का मोर्चा भी अकेले लड़ने की तैयारी कर रहा है। 2016 के बाद पहली बार ऐसी स्थिति बन रही है। पिछले दो चुनावों में कांग्रेस और वाम मोर्चे के बीच सीट एडजस्टमेंट की सहमति बनी थी और दोनों ने मिल कर चुनाव लड़ा था। पिछली बार यानी 2021 में तो फुरफुराशरीरक के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी आईएसएफ के साथ भी सीटों का समझौता हुआ था। इस बार देखने वाली बात होगी कि आईएसएफ की कमान संभाल रहे नौशाद सिद्दीकी क्या फैसला करते हैं। उनका फैसला इसलिए अहम हो गया है क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में एक मुस्लिम गठजोड़ के अलग से चुनाव लड़ने की संभावना बन रही है। तृणमूल से चुनाव जीते हुमायूं कबीर ने जनात उन्नयन पार्टी बनाई है। वे मुर्शिदाबाद के बेलदांगा में बाबरी मस्जिद बनवा

रहे हैं और मुस्लिम ध्ववीकरण के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों एक सभा की तो उसमें असदुद्दीन औवैसी की पार्टी ऑल इंडिया एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष इरफान सोलंकी भी शामिल हुए थे। कहा जा रहा है कि हुमायूं कबीर इस बार औवैसी की पार्टी एमआईएम और बदरुद्दीन अजमल की पार्टी एआईयूडीएफ से तालमेल करेंगे। अगर आईएसएफ इसमें शामिल हो तो चार मुस्लिम पार्टियों का एक मोर्चा बनेगा। हालांकि इस बीच यह भी खबर है कि सीपीएम के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी हुमायूं कबीर से मुलाकात की है। तो क्या लेफ्ट मोर्चा इन मुस्लिम पार्टियों के साथ गठबंधन कर सकता है? जो हो अभी तक यह दिख रहा है कि भाजपा और तृणमूल कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई में कांग्रेस, लेफ्ट और मुस्लिम पार्टियों के मोर्चे की चुनौती है। दूर से एक बहुकोणीय मुकाबला दिख रहा है। हालांकि ऐसा होगा नहीं। चुनाव से पहले बन रहे गठबंधनों की पुष्टभूमि जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम दोनों बोटों के बंटवारे या ध्ववीकरण से चुनावी नतीजे तय होते हैं। लगभग 30 फीसदी मुस्लिम आबादी लगभग पूरी तरह से ममता बनर्जी की पार्टी के समर्थन में वोट करती है। दूसरी ओर 70 फीसदी हिंदू आबादी का लगभग 60 फीसदी हिस्सा भाजपा का समर्थन करता है। इसका अर्थ है कि अगर 10 फीसदी और हिंदू वोट भाजपा के साथ जुड़ जाए तो भाजपा चुनाव जीत जाएगी या अगर 20 फीसदी के करीब मुस्लिम वोट ममता बनर्जी से टूट जाए तब भी भाजपा जीत जाएगी। भाजपा का 38 से 40 फीसदी तक वोट कायम रहने की संभावना इसलिए है क्योंकि पिछले तीन चुनावों में उसे इतना ही वोट मिलता है और उसे इसे और कंसोलिडेट किया है। पिछले चुनाव में कांग्रेस, लेफ्ट और आईएसएफ को साझा तौर पर 12 फीसदी के करीब वोट मिला था। इसमें ज्यादा बड़ा हिस्सा हिंदू वोट का था। ध्यान रहे बांग्ला बोलने वाला हिंदू समुदाय भाजपा के साथ

जाने की बजाय ममता बनर्जी या लेफ्ट, कांग्रेस के साथ रहता है। लेकिन इस बार स्थिति बदलने की संभावना है। बांग्लाभाषी हिंदू पहली बार मुस्लिम आबादी को लेकर चिंता में हैं। उनको लग रहा है कि भाषा और संस्कृति की एकता बनाने के चक्र में बांग्लाभाषी हिंदू पहले कांग्रेस फिर लेफ्ट और अब तृणमूल को वोट देते रहे हैं लेकिन इस बीच राज्य की जनसंख्या संरचना बदल गई और उनके सामने गंभीर खतर खड़े हो गए हैं। अगर बांग्लाभाषी हिंदू इस मानसिकता में वोट करते हैं तो भाजपा के लिए अवसर बनेगा और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू ध्ववीकरण मजबूत होगा। अगर चुनिंदा इलाकों में जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर के मुस्लिम बहुल इलाकों में तृणमूल कांग्रेस को छोड़ कर मुस्लिम आवाम का समर्थन मुस्लिम नेताओं की पार्टियों को मिलता है तो हैदराबाद से शुरू होकर महाराष्ट्र और बिहार तक मुस्लिम नेतृत्व के प्रति मुस्लिम आवाम के बढ़ते रूझान पर मुहर लगेगी। यह ट्रेड स्थायी रूप से देश की राजनीति को बदलने वाला होगा। ध्यान रहे बिहार में आमने सामने के चुनाव के बावजूद औवैसी की पार्टी के पांच विधायक जीते। महाराष्ट्र में औवैसी की पार्टी के करीब एक सौ पार्षद जीते हैं। यह ट्रेड दिखाता है कि मुस्लिम आवाम के मन में मौजूदा सेकुलर पार्टियों को लेकर संदेह पैदा हो गया है। वे उनकी बजाय सीधे अपना नेतृत्व खड़ा करना चाहते हैं। तभी जहां भी उनको अपना विकल्प मिलता है वे उसे प्राथमिकता देते हैं। जहां विकल्प नहीं है वहां रणनीतिक मजबूरी में कांग्रेस या किसी प्रादेशिक पार्टी का समर्थन करते हैं। अगर ममता बनर्जी की पार्टी को मुसलमानों का समर्थन कम होता है तो इस ट्रेड की पुष्टि होगी। आगे के चुनावों में देश के दूसरे हिस्सों में भी यह ट्रेड देखने को मिलेगा। नेतृत्व के स्तर पर भी पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजे का असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। अगर ममता बनर्जी चौथी बार जीतीं हैं और लगातार दूसरी

बार सीधे मुकाबले में भाजपा को हराती हैं तो इसे भाजपा के मौजूदा नेतृत्व के करिश्मे और रणनीति के क्षरण की शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा। ध्यान रहे एनडीए के अंदर वैसे भी इस बार भाजपा की स्थिति कमजोर है। पिछले चुनाव में वह अकेले दम पर बहुमत नहीं हासिल कर पाई। नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के समर्थन पर निर्भर है। पश्चिम बंगाल में हारने पर सहयोगी पार्टियों का दबाव बढ़ेगा और पार्टी के अंदर भी एक दबाव समूह उभर सकता है। संघ की ओर से दखल बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर पश्चिम बंगाल का किला भाजपा फतह कर लेती है तो फिर राष्ट्रीय राजनीति में वह अजेय हो जाएगी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व के सामने लंबे समय तक कोई चुनौती नहीं आएगी। पश्चिम बंगाल के नतीजे का विपक्षी गठबंधन पर भी बड़ा असर होगा। अगर ममता बनर्जी जीतीं हैं तो फिर जैसा कि अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा से लड़ने वाली इकलौती नेता के तौर वे स्थापित होंगी। वे दिल्ली कूच करेंगी। राहुल गांधी के नेतृत्व के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होगी। उनके पीछे हटने और ममता बनर्जी के नेतृत्व में 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी करने की मांग उठेगी। यह मांग जमीन सचाइयों पर आधारित होगी। इसलिए कांग्रेस भले विरोध करे पर दूसरी पार्टियां इस पर गंभीरता से विचार करेंगी। ध्यान रहे अगले चुनाव तक विपक्षी पार्टियों का सत्ता का सूखा 15 साल का हो जाएगा। ऐसे में वे ममता बनर्जी के ऊपर दांव लगा सकती हैं। अगर कांग्रेस केरल और असम में जीत जाती है और तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन जीतता है तब भी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व को लेकर गंभीर चर्चा छिड़ेगी। कुछ मिला कर हिंदू ध्ववीकरण, मुसलमानों के अंदर अपने नेतृत्व की तलाश की बेचैनी और एनडीए व 'इंडिया' ब्लॉक में नेतृत्व के लिहाज से पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत अहम होने वाला है।



भगवान की आरती करने का सही तरीका क्या है?



अक्सर आपने देगा होगा कि देवी और देवताओं की आरती घी के दीपक या कपूर से करते हैं। इस दौरान संबंधित देवी और देवता की आरती भी गाते हैं और आरती की थाल को देवताओं के सामने घुमाते भी हैं। लेकिन इसे घुमाने का भी तरीका शास्त्रों में बताया गया है।

कितनी बार घुमाएं आरती की थाल

धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक आरती की शुरुआत में हमेशा भगवान चरणों से करनी चाहिए। उनके चरणों में थाली को चार बार घुमाना शुभ माना जाता है। इसके तुरंत बाद भगवान की नाभि की ओर दो बार थाल को घुमाना सही माना जाता है। फिर भगवान के चेहरे के सामने आरती करनी चाहिए। इस बार थाल सिर्फ एक बार घुमाना है। आखिरी में भगवान के पूरे शरीर पर आरती की थाली सात बार घुमाना चाहिए। माना जाता है कि इस तरह कुल 14 बार आरती घुमाने से चौदह भुवनों तक आपकी भक्ति पहुंचती है।

आरती करते समय ध्यान रखें ये बातें

- आरती हमेशा खड़े होकर करना चाहिए। बैठकर आरती कभी नहीं करना चाहिए।
- आरती हमेशा झुककर करना चाहिए। इसे भक्ति का प्रतीक माना जाता है।
- आरती की थाली सही धातु की हो- तांबे, पीतल या चांदी की थाली में आरती करें।

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व

हिंदू धर्म में पूजा-पाठ का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित पूजा-पाठ होता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन कोई भी पूजा बिना आरती के अर्पणी मानी जाती है। भगवान की आरती का खास महत्व होता है। यह भक्ति, ध्यान और समर्पण के भाव को दर्शाता है। मान्यता है कि अगर आरती सही विधि और मन से की जाए, तो इससे कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन बहुत से कम लोग जानते हैं कि आरती करने का भी एक सही तरीका होता है। चलिए आज जानते हैं कि आरती का सही तरीका क्या है और इससे लाभ क्या है।

- आरती करने के लिए गाय के घी में डूबी हुई रुई की 5 बलियों का दीपक जलाएं। इसे पंच प्रदीप कहा जाता है।

आरती से लाभ

- आरती से मन की नकारात्मकता कम होती है और मन शांत होता है।
- आरती के दौरान दीपक और मंत्रों से वातावरण शुद्ध होता है।
- नियमित आरती करने से ध्यान और आत्म-नियंत्रण मजबूत होता है।
- मान्यता है कि नियमित आरती से घर में शांति और शुभता बनी रहती है।

प्राइमर :- एक बार जब आप चेहरा धो कर मॉइश्चराइजर लगा लेते हैं तो अपनी स्किन को तैयार करने और अपने मेकअप को बेहतर दिखाने के लिए प्राइमर का इस्तेमाल करें। प्राइमर बड़े रोमछिद्रों को कम कर सकता है और आपके मेकअप को लंबे समय तक टिकाए रख सकता है। इन दिनों कुछ प्राइमर ऐसा भी आ रहे हैं जो फिल्टर वाला लुक देते हैं तो आप इस तरह के प्राइमर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

फाउंडेशन :- ऑफिस मेकअप में हल्के और लंबे समय तक टिकने वाले फाउंडेशन का इस्तेमाल करें जो आपकी स्किन के रंग से मैच होता हो।



कंसिलर :- दाग-धब्बों और काले धेरों को छिपाने के लिए कंसिलर का इस्तेमाल करें।

आईलाइनर :- ऑफिस मेकअप में जेल बेसड आईलाइनर का इस्तेमाल करें। ये आसानी से खराब नहीं होगा। अच्छे लुक के लिए



ऑफिस के लिए हर महिला अपने मुताबिक तैयार होकर जाती है। ऐसे में एक चीज जो सभी में कॉमन होती है वह है मेकअप। मेकअप और ड्रेसिंग सेंस से लड़कियों का आत्म विश्वास काफी बढ़ जाता है। हालांकि, ऑफिस के लिए कैसा मेकअप करें इसे लेकर ज्यादातर लड़कियों को कंप्यूजन रहती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार मेकअप डार्क हो जाता है या फिर कई बार बहुत लाइट हो जाता है। ऐसे में आज हम आपको ऑफिशियल मेकअप करने का सही तरीका बता रहे हैं। अगर आप यहां बताए गए मेकअप स्टेप्स को अपनाएं तो 10 मिनट में मेकअप करके तैयार हो जाएंगी।

10 मिनट में करें परफेक्ट मेकअप

आईलाइनर की एक पतली लेयर लगाएं और फिर इसे थोड़ा स्मज कर दें।

ब्लश :- अपने गालों और नाक के ऊपरी हिस्से पर थोड़ी ब्लश लगाएं। बहुत ज्यादा डार्क रंग का ब्लश लगाने से बचें। ऑफिस लुक में

नैचुरल रंग का ब्लश ही अच्छा लगता है।

होंट :- अपने होंटों को लिप कलर से भरें। ऑफिस के लिए आप हल्के रंगों को ही चुनें।

आंखें :- ट्रांसपेरेंट मस्कारा लगाकर ऑफिस मेकअप लुक को पूरा करें।

घर में ड्राइंग रूम किस दिशा में बनवाना चाहिए ?



वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का निर्माण किया जाता है। कई बार जाने-अजाने में गलत दिशा में घर या कमरा बनवाने से वास्तु दोष का प्रभाव बना रहता है। घर का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है लिविंग रूम। घर के ड्राइंग रूम में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखना बेहद जरूरी है। सिर्फ मेहमान ही नहीं घर के सदस्य भी ड्राइंग रूम का इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं ड्राइंग रूम किस दिशा में बनवाना चाहिए व ड्राइंग रूम से जुड़े कुछ वास्तु टिप्स-



वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर में ड्राइंग रूम उत्तर-पूर्व अथवा उत्तर-पश्चिम दिशा में होना या बनवाना शुभ माना जाता है। ड्राइंग रूम का निर्माण इस तरीके से करवाना चाहिए की सूर्य की रोशनी कमरे में आती रहे। कमरे में जितना प्राकृतिक प्रकाश आएगा उतना ही शुभ रहेगा। ड्राइंग रूम में सोफा आदि दक्षिण अथवा पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। हल्का फर्नीचर उत्तर एवं पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ड्राइंग रूम का ईशान कोण यथा संभव खाली या बहुत हल्का होना

चाहिए यानि इस दिशा में ज्यादा सामान नहीं रखना चाहिए। ड्राइंग रूम में पूर्व एवं उत्तर दिशा में खिड़की होना आवश्यक है। ड्राइंग रूम की दीवारों पर हल्के रंग का पेंट करवाना अच्छा माना जाता है। ड्राइंग रूम में सेंटर टेबल पर एक क्रिस्टल का लोटस रखना शुभ फलदायी होता है। ड्राइंग रूम का पंटी गेट उत्तर या पूर्व की दिशा में होना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं, ड्राइंग रूम के अंदर उत्तर या पूरब की दिशा में खिड़कियां होना बेहद शुभ माना जाता है।

ठंड में दमकती त्वचा के लिए अपनाएं आयुर्वेदिक स्किन केयर

क्योंकि इस समय सभी के शरीर में ज्यादा ताकत होती है। सर्दियों के दौरान सूरज की रोशनी में शरीर की क्षमता के अनुसार व्यायाम करने से आपको पूरे दिन गर्म और एनर्जेटिक रहने में मदद मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यायाम आपके शरीर की अग्नि को उत्तेजित करता है जो आपकी स्किन को गर्म रखता है और पाचन क्षमता को बढ़ाता है।

1) अभ्यंग

आयुर्वेद सर्दियों के दौरान नियमित अभ्यंग यानी तेल मालिश का सुझाव देता है। इससे करवाने पर कई फायदे मिलते हैं, जिनमें उम्र बढ़ने में देरी, थकान से राहत और वात दोष यानी दर्द को शांत करता है। ये सर्दियों में काफी असरदार होता है और स्किन की ड्राईनेस को खत्म कर सकता है।

2) अटापा-सेवना

सर्दियों के दौरान सुबह की सूरज की किरणों के संपर्क में आना आरामदायक होता है। ऐसे में आयुर्वेद सुझाव देता है अटापा-सेवन यानी अभ्यंग के बाद जो आपकी स्किन में तेल के उचित अवशोषण में मदद करता है। इसी के साथ विटामिन डी पाने में मदद करता है।

3) व्यायाम

व्यायाम करने के लिए सर्दी सबसे अच्छा मौसम है।

4) स्नान

आयुर्वेद सर्दियों के दौरान गुनगुने पानी से स्नान करने का सुझाव देता है। हालांकि, गर्म पानी से नहाने से क्योंकि ये आपकी स्किन ड्राईनेस को बढ़ा देता है और आपकी स्किन ज्यादा ड्राई हो जाती है और फटने

आयुर्वेद में हर समस्या से निपटने का इलाज है, अच्छी बात यह है कि ये इलाज नैचुरल है। जिसे हर कोई फॉलो कर सकता है। बात स्किन केयर की करें तो आयुर्वेद में त्वचा देखरेख का मतलब स्किन डिटॉक्स करने और ब्लड सर्कुलेशन सही रखने से है। सर्दियों में स्किन की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है ड्राईनेस, इससे निपटने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक तरीकों को अपना सकते हैं। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर के अनुसार इन तरीकों के बारे में बताया गया है, जानिए।



का खतरा होता है, इसलिए सर्दियों में गर्म पानी के बजाय गुनगुने पानी से नहाने को चुनना सबसे अच्छा है।

5) नस्य

नस्य मतलब नाक में औषधीय तेल डालना। यह सिरदर्द, माइग्रेन, साइनस कंजेशन, एलर्जी, नाक से खून आना, सफेद बाल, बालों का झड़ना, अनिद्रा आदि में मदद करता है। सोते समय दोनों नाक में A2 गाय का घी या तिल का तेल की 2 बूंद डालने से सर्दियों में अच्छी नींद आती है।

6) पाद-अभ्यंग

घी, तिल या सरसों के तेल से पैरों की मालिश करें। ऐसा करके आपके तलवों को फटने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा आपके दिमाग और शरीर को आराम मिलता है और ब्लड फ्लो में सुधार होता है।

हाई बीपी को नेचुरली कंट्रोल रखते हैं ये योगासन

बिगडी हुई लाइफस्टाइल, खानपान की खराब आदतें और जल्द से ज्यादा तनाव, आज ज्यादातर लोगों के लिए हाई बीपी का कारण बनता जा रहा है। लंबे समय तक बना हुआ हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और किडनी फेलियर जैसी गंभीर समस्याओं को जन्म देता है। यही तजह है कि इस समस्या को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप भी हाई बीपी की समस्या से परेशान हैं तो अपने डेली रूटीन में योग को जरूर जगह दीजिए। नियमित रूप से योगासन करने से हाई बीपी को कंट्रोल रखने में मदद मिल सकती है। योग न केवल तंत्रिकाओं को शांत करता है, बल्कि तनाव दूर करके बीपी को नेचुरली कंट्रोल करने में भी मदद करता है। आइए जानते हैं ऐसे ही दो योगासनों के बारे में, जिनका नियमित अभ्यास आपके बीपी को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है।

सेतुबंधासन
सेतुबंधासन को अंग्रेजी में ब्रिज पोज के नाम से भी जाना जाता है। यह आसन न केवल ब्लड प्रेशर को प्रभावी ढंग से कम करने में मदद करता है, बल्कि गटिया के दर्द में भी राहत देकर मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। इस आसन को करते समय साधक को अपनी गर्दन, रीढ़ और चेस्ट में स्ट्रेच महसूस होता है। जिससे उसे अपनी परेशानियों में आराम मिलता है।



सेतुबंधासन करने का तरीका
सेतुबंधासन करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल सीधा लेटकर घुटनों और कोहनीयों को मोड़ें। इसके बाद अपने पैरों को फर्श पर कूल्हों के पास और अपने हाथों को सिर के दोनों तरफ मजबूती से रखें। अब अपने दोनों हाथों और पैरों को जमीन पर सहारा देते हुए धीरे-धीरे शरीर को हवा में उठाने की कोशिश करें। ऐसा करते हुए आपका शरीर ब्रिज के समान बन जाएगा। अब इस मुद्रा में 20 सेकंड के लिए बने रहें। तय समय बाद धीरे-धीरे शरीर को पहले की मुद्रा में वापस ले आएं।

दही (Curd) इंडियन फूड का अहम हिस्सा है। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स पाचन को मजबूत करते हैं और इम्युनिटी बढ़ाते हैं, लेकिन सर्दियों

दही खाने का सही तरीका क्या है?



में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या ठंड के मौसम में दही खाना सही है? कहीं यह सर्दी-खांसी तो नहीं बढ़ाता? आयुर्वेद के अनुसार दही का सेवन सही तरीके और सही समय पर किया जाए तो यह नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही देता है।

जानें फायदे

(सुखी अदरक) मिलाएं। दही को मछु (छाछ) बनाकर पीना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। दही के साथ चावल या रात का भोजन अवॉइड करें।
दही शरीर के लिए ठंडा या गर्म होता है?
आयुर्वेद के अनुसार दही की तासीर ठंडी नहीं बल्कि भारी (गुरु) होती है। यह कफ बढ़ाने वाली होती है, इसलिए ठंड के मौसम में अधिक मात्रा में दही खाने से बलगम की समस्या हो सकती है।
क्या सर्दी-खांसी में दही खाना ठीक है?
नहीं, अगर आपको - सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश है, तो दही से परहेज करना चाहिए। दही कफ को खाने से पहले इसमें काली मिर्च, भुना जीरा या सोंठ बढ़ा सकती है और समस्या को लंबा खींच सकती है।



आयुर्वेद के अनुसार दही खाने का सबसे अच्छा समय क्या है?

दोपहर (Lunch time) दही खाने का सबसे अच्छा समय है। सुबह खाली पेट और रात में दही खाना आयुर्वेद में वर्जित माना गया है। दिन में पाचन अग्नि मजबूत होती है, जिससे दही आसानी से पच जाती है।
दही खाते समय क्या सावधानियां बरतें?
रात में दही न खाएं। दही + दूध का कॉम्बिनेशन न लें। बहुत खड़ी दही अवॉइड करें। बच्चों और बुजुर्गों को सीमित मात्रा में दें।

लड्डू बनाते समय कुछ आसान कुकिंग टिप्स

अनुपात का रखें ध्यान
लड्डू बनाते समय सबसे पहले उसमें डाली जाने वाली हर चीज के सही अनुपात का ध्यान रखें। आटे में घी की मात्रा कम रहने से लड्डू सख्त बनते हैं। ऐसे में लड्डू बनाते समय घी की मात्रा की खास ख्याल रखें। लड्डू में पर्याप्त मात्रा में डाला गया घी उन्हें नरम बनाता है।
मीठा डालते हुए
लड्डू में मिठास बनाए रखने के लिए उसमें चीनी या गुड़ का मिश्रण डालने से पहले कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें। अगर आप लड्डू में पाउडर चीनी का यूज कर रहे हैं, तो इसे लड्डू के टंडे मिश्रण में मिलाएं। जबकि गुड़ का यूज करने पर इसे घी में हल्का पिघलाकर डालें। चीनी की चाशनी डालते समय ध्यान रखें कि एक तार की चाशनी लड्डू को सॉफ्ट बनाए रखती है।
सही तरह से भूना हुआ हो लड्डू का मिश्रण
अगर लड्डू के बेसन या आटे की भुनाई अच्छी तरह से नहीं होती है तो लड्डू के स्वाद में कच्चापन आने के साथ वो सख्त भी बनते हैं। इस बात का खास ख्याल रखें कि लड्डू का आटा हमेशा धीमी आंच पर भूना जाता है, जिससे वो अंदर तक पक जाता है। आटे को लो फ्लेम पर तब तक भूनें, जब तक उसका रंग हल्का भूरा होने के साथ अच्छी खुशबू ना देने लगे।



खबर-खास

चाकू टिकाकर नगदी रकम लूट करने वाला आरोपी गिरफ्तार

रायपुर। प्रार्थी मनीष कुमार यदु निवासी ग्राम सुरपा थाना आर. जामगांव, जिला दुर्ग ने थाना आजाद चौक में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 20.02.2026 को वह मंदिर हसीद चौक से एक मोटरसाइकिल चालक के साथ लिफ्ट लेकर रायपुर आ रहा था। रास्ते में मोटर सायकल के चालक ने उसे शराब पिलाने हेतु कहा। दोनों लाखे नगर चौक पहुंचे, जहां वह प्रार्थी को उतारकर ईदगाहभाटा स्थित अपने ससुराल जाने की बात कही। कुछ समय बाद वह अपने मित्र कबीर के साथ वापस आया और प्रार्थी को सरोना स्थित जायका शोरूम छोड़ने मोटरसाइकिल में बैठाकर ले गये। रात्रि लगभग 01:00 बजे मुकुट नगर के आगे एक सुनसान गली में मोटरसाइकिल रोककर दोनों आरोपियों ने प्रार्थी से पैसे की मांग की। प्रार्थी द्वारा पैसे नहीं होने की बात कहने पर दोनों ने उसे पकड़ लिया, चाकू पेट पर टिकाकर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपये लूट लिए, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना आजाद चौक में अपराध क्रमांक 46/25, धारा 309(4) बीएनएस एवं धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। उक्त घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस उपयुक्त (पश्चिम क्षेत्र) रायपुर संदीप पटेल द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों एवं थाना प्रभारी को आरोपियों की पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी आजाद चौक के नेतृत्व में थाना आजाद चौक पुलिस की टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपियों के छिपने के हर संभावित स्थानों में रेंड कार्यवाही करते हुये प्रकरण में आरोपी शेष कबीर को पकड़कर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी शेष कबीर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूट की नगदी रकम 1500/- रुपये एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग चाकू जप्त कर आरोपी को जेल भेजा गया। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी फार है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम शेष कबीर पिता शेष नासिर उम्र 22 साल निवासी ईदगाहभाटा थाना आजाद चौक रायपुर।

पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, अपर सत्र न्यायाधीश दुलार सिंह निर्मलकर ने सुनाया फैसला, उर्ताई थाना क्षेत्र के ग्राम मर्गा का मामला

पाटन। उर्ताई थाना क्षेत्र के ग्राम मर्गा में पत्नी की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश पाटन दुलार सिंह निर्मलकर की अदालत ने आरोपी गोपी राम यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शासन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक शेखर वर्मा ने पैरवी की।

इस बार प्राकृतिक रंगों से रंगीन होगी होली

समूह की महिलाएं पलास, चुकंदर एवं पालक के पत्तों से बना रही हर्बल गुलाल

गरियाबंद (विश्व परिवार)। जिले में रंगों के त्योहार होली को स्वसहायता समूह की महिलाएं इस बार और खास बना रही हैं। होली के त्योहार को प्राकृतिक रंगों से मनाने के लिए महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं। ग्राम सड़ौली की राखी महिला ग्राम संगठन की 10 सक्रिय महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत हर्बल गुलाल का निर्माण कर आत्मनिर्भरता और

स्वावलंबन को मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं पलास से पीला, चुकंदर से लाल और पालक के पत्तों से हरा रंग निकालकर मक्के की सूखी डंठल से प्राप्त अरारोट पाउडर में मिलाकर प्राकृतिक गुलाल का निर्माण कर रही हैं। इसमें हानिकारक रसायनिक तत्वों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता जिससे हर्बल गुलाल त्वचा एवं सेहत के लिए सुरक्षित रहता है। राखी महिला ग्राम संगठन की ये महिलाएं न केवल होली के त्योहार को प्राकृतिक और सुरक्षित बना रही हैं, बल्कि अपनी आजीविका को भी मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री



विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम

साबित हो रही है। इलेक्टर बीएस उड़के एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रखर चंद्राकर ने भी इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्वल भविष्य को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज महिलाएं स्वरोजगार सृजित कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। पीआरपी मीना साहू ने बताया कि पिछले वर्ष भी बिहान समुह के दीदियों द्वारा कुल 30 हजार रुपये से अधिक की बिक्री कर लगभग 10 हजार रुपये से अधिक की शुद्ध मुनाफा अर्जित की थी। समूह की महिलाओं से

चर्चा के फलस्वरूप पारंपरिक तरीकों से बनाए गए प्राकृतिक गुलाल से न केवल सेहत स्वस्थ रहेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए आसानी का नया स्रोत भी बन रहा है। पिछले वर्ष हर्बल गुलाल की मांग अधिक रही, जिसे देखते हुए इस बार पहचान बना रही है। पीआरपी मीना साहू ने बताया कि पिछले वर्ष भी बिहान समुह के दीदियों द्वारा कुल 30 हजार रुपये से अधिक की बिक्री कर लगभग 10 हजार रुपये से अधिक की शुद्ध मुनाफा अर्जित की थी। समूह की महिलाओं से

क्या यही है ज्ञान, गति का संकल्प? – NHM कर्मचारियों की उपेक्षा पर सवाल

गरियाबंद (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्तुत बजट का थीम ज्ञान के उत्थान, गति की शक्ति से, संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए रखा गया है। प्रदेश अध्यक्ष डॉ अमित मिश्र और गरियाबंद जिलाध्यक्ष अमृत राव भोंसले ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह थीम राज्य के समग्र विकास और जनकल्याण की दिशा में सकारात्मक संदेश देता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की विशेष घोषणा या ठोस पहल नहीं की गई। जिला प्रवक्ता और प्रांतीय प्रतिनिधि भूपेंद्र सिन्हा और भूपेश साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ माने जाने वाले NHM कर्मचारी वर्षों से सीमित वेतन, अनिश्चित भविष्य और अस्थिर सेवा शर्तों के बावजूद पूरे समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। कोविड काल सहित विभिन्न स्वास्थ्य चुनौतियों के समय इन कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद बजट में इनके हितों की अनदेखी कई सवाल खड़े करती है। कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर महतो और शेखर धुर्वे ने कहा कि विशेष रूप से यह भी स्मरणीय है कि नरेंद्र मोदी के नाम से जारी

मोदी की गारंटी में संविदा कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का स्पष्ट संकल्प व्यक्त किया गया था। ऐसे में NHM कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि इस बजट में उनके नियमितकरण, वेतन संरचना में सुधार या सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ठोस निर्णय सामने आएंगे। NHM कर्मचारी संघ का मानना है कि यदि राज्य सरकार वास्तव में ज्ञान के उत्थान और गति की शक्ति के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेती है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने वाले इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता में होना चाहिए। राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि: NHM संविदा कर्मचारियों के नियमितकरण की दिशा में ठोस नीति बनाई जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा 19 सितम्बर 2025 को किये गए घोषणा की 3 माह के भीतर चिकित्सा बीमा, ग्रेड पे, एच आर पालिसी में सुधार, अनुकम्पा नियुक्ति एवं अन्य मांगों को समयबद्ध पूर्ण करने एवं 17500 कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सेवा स्थिरता प्रदान की जाए। अंततः प्रश्न यही है — क्या यही है ज्ञान के उत्थान और गति की शक्ति का संकल्प, जब स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वाले कर्मचारियों की ही अनदेखी की जाए?

वार्ड 44 में महापौर का निरीक्षण, रहवासियों से किया सीधा संवाद

दुर्ग। नगर पालिक निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 44 में महापौर अलका बाघमार ने क्षेत्र का निरीक्षण कर विकास कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वार्ड के रहवासियों से सीधे रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और आवश्यक निर्देश दिए। महापौर ने कहा कि नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है और किसी भी वार्ड में बुनियादी सुविधाओं की कमी नहीं रहने दी जाएगी। 40 वर्षों से पानी की समस्या से जूझ रहे थे नागरिक .. निरीक्षण के दौरान वार्डवासियों ने महापौर को बताया कि वे पिछले लगभग 40 वर्षों से पेयजल संकट की समस्या से जूझ रहे थे। नियमित एवं पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। गर्मी के मौसम में स्थिति और भी बिगड़ती जाती थी, जिससे महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष रूप से कठिनाई उठानी पड़ती थी। वार्डवासियों की पीड़ा को गंभीरता से लेते हुए महापौर अलका बाघमार ने तत्काल अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और पानी की समस्या के स्थायी समाधान हेतु कार्य प्रारंभ कराया। निगम प्रशासन की पहल से वार्ड 44 में पेयजल व्यवस्था को सुचारू किया गया, जिससे लंबे समय से चली आ रही समस्या का निराकरण संभव हो सका। महापौर ने कहा कि शहर के प्रत्येक वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है। पार्श्व एवं महिलाओं ने बताया कि वार्ड 44 में पार्श्व सहित क्षेत्र की महिलाओं एवं नागरिकों ने महापौर का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से चली आ रही समस्या का समाधान होने से वार्डवासियों को बड़ी राहत मिली है।

नई कहानी लिख रही हैं। यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं गंगा अनंत (Ganga Anant) पिता श्री जे पी अनंता (JP Ananta), उम्र 36 वर्ष, निवासी ई.डब्ल्यू.एस. 1917, विश्व बैंक कालोनी, कुरुद थिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) 490024 यह शपथ करती हूँ कि मैंने अपना यह पुराना नाम गंगा (Ganga) को त्यागकर नया नाम गंगा अनंत (Ganga Anant) रख ली हूँ। अतः आज से मेरे समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय / विधायक संस्थान व अन्य दस्तावेजों में मेरा नया नाम गंगा अनंत (Ganga Anant) से ही जाना, पहचाना, व पुकारा जावे। गंगा अनंत पिता श्री जे पी अनंता उम्र 36 वर्ष, निवासी- ई.डब्ल्यूएस.-1917, विश्व बैंक कालोनी, कुरुद थिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) 490024

जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के महामंत्री बने जामवंत गजपाल

दुर्ग। जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने अपनी कार्यकारणी की घोषणा की, जिसे अनुमोदित किया प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैँड़ ने। कार्यकारणी में पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग ग्रामीण के सचिव रहे कर्मठ ऊर्जावान एवं पार्टी के प्रति निष्ठावान कार्यकर्ता जामवंत गजपाल (करगाडीह)को महामंत्री बनाया गया। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू,जनपद उपाध्यक्ष राकेश हिरवानी, ब्लाक अध्यक्ष देवेन्द्र देशमुख, समाज सेवी सुभाष साव, हर्ष साहू, नंद कुमार गजपाल, परिक्षेत्र अध्यक्ष घनश्याम गजपाल, डिक्केन्द्र हिरवानी, रूपेन्द्र साहू, गजानंद साहू, पूर्व मंडी अध्यक्ष दुर्ग अश्वनी साहू, रामेश्वर साहू, संतोष साहू, बिहारी लाल देवांगन, चिंतामणि गजपाल, नील कुमार साहू, भैकचंद साहू, कोशल साहू, नीतिरंज साहू, नीलमणि साहू शेखर साहू, हिंछा साहू, बिसलाल साहू, राजेन्द्र साहू, पुष्पेन्द्र साहू, ढालेश्वर यादव, महेंद्र यादव, कृष्णा साहू, प्यारे लाल बघेल, गजेन्द्र साहू, किशोर गजपाल, शशि साहू और किशोर साहू ने हर्ष जताया है।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा 19 सितम्बर 2025 को किये गए घोषणा की 3 माह के भीतर चिकित्सा बीमा, ग्रेड पे, एच आर पालिसी में सुधार, अनुकम्पा नियुक्ति एवं अन्य मांगों को समयबद्ध पूर्ण करने एवं 17500 कार्यरत कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और सेवा स्थिरता प्रदान की जाए। अंततः प्रश्न यही है — क्या यही है ज्ञान के उत्थान और गति की शक्ति का संकल्प, जब स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने वाले कर्मचारियों की ही अनदेखी की जाए?

कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग

नामांतरण सूचना विज्ञप्ति क्रमांक 53 वर्ष 2025-26

सर्व साधारण को सूचना दी जाती है कि छ.ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 धारा 167 के अंतर्गत निम्नलिखित व्यक्तियों के उनके नाम के सामने भुमि/भवन स्वामित्व परिवर्तन हेतु आवेदन किया है।

संबंधित हित वाले व्यक्ति सूचना प्रकाशन के 15 दिनों के अंदर अपने आपत्ति लिखित में अधोहस्ताक्षरों के कार्यालय में प्रस्तुत करें। समयवधि के पश्चात आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्रं	ना.प्र.क्र.	क्रेता का नाम	विक्रेता का नाम	वार्ड क्रमांक	नाम परिवर्तन का आधार जिस पर दावा/आपत्ति की जाती है
1149	1149	साईंस्ता खान/मोहम्मद इमरान खान	मोहम्मद अली/अकबर अली	वार्ड क्र.49 बोरसी(पश्चिम) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1150	1150	सनदीप सिंग भामरा/स्व. सरदार अजीत सिंग भामरा	जोगिंदर कौर/अजीत सिंह	वार्ड क्र.28, पचरोपारा दुर्ग	व्यवस्थानामा लिखित
1151	1151	परशुराम गनवारे/जेतुराम गनवारे	पाना देवी/पप्पुनाथ	वार्ड क्र.51 बोरसी (उत्तर), दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1152	1152	प्रदीप कुमार गुप्ता/बी.पी.गुप्ता, कंचन गुप्ता/प्रदीप कुमार गुप्ता	मेसेस आई स्कवेयर ईफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एम.जी.गिरीश/एम.एन. गोपालन, एन.एल.गुप्ता/एन.बी. लालसन	वार्ड क्र. 60,कालुलबोर्ड (पश्चिम) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1153	1153	कृष्णा गुप्ता/भोला प्रसाद गुप्ता	मेसेस आई स्कवेयर ईफ्रास्ट्रक्चर पार्ट एम.जी.गिरीश/एम.एन. गोपालन, एन.	वार्ड क्र. 60,कालुलबोर्ड (पश्चिम) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1154	1154	प्रदीप कुमार गुप्ता/भोला प्रसाद गुप्ता	शांति स्वरूप वर्मा/पृथ्वी सिंह वर्मा डॉ संजीव भोला गुप्ता/भोला प्रसाद गुप्ता	वार्ड क्र. 60,कालुलबोर्ड (पश्चिम) दुर्ग	दान पत्र
1155	1155	देवकी साहू/समारू साहू	राजू भोसले/स्व. के.एच.भोसले, सीता भोसले/स्व. एच भोसले	वार्ड क्र.19,शहीद भगत सिंह(दक्षिण) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1156	1156	आशीष कुमार सिंह/ अरूण कुमार सिंह	अशोक दत्ता/जुवराज दत्ता	वार्ड क्र.53, पोटियकला (उत्तर) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1157	1157	टोपनमल/गोविन्दराम मोहनानी	हरिराम मोहनानी/टहकन मल मोहनानी	वार्ड क्र.27 पोलसाय पारा दुर्ग	बंटवारनामा
1158	1158	आसनदास मोहनानी/टोपनमल मोहनानी	हरिराम मोहनानी/टहकन मल मोहनानी	वार्ड क्र.27 पोलसाय पारा दुर्ग	बंटवारनामा
1159	1159	मुकेश कुमार मोहनानी/टोपनमल मोहनानी	हरिराम मोहनानी/टहकन मल मोहनानी	वार्ड क्र.27 पोलसाय पारा दुर्ग	बंटवारनामा
1160	1160	मंजू देवांगन/राजेश देवांगन	सीमा देवांगन/शैलेन्द्र देवांगन	वार्ड क्र.56,बघेरा दुर्ग	बंटवारनामा
1161	1161	कविता विश्वकर्मा/संजय कुमार विश्वकर्मा साहू	लोकेश्वर कुमार साहू/जिवराखन साहू	वार्ड क्र.52, बोरसी (दक्षिण) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1162	1162	विशुन देव राम/मिश्री लाल राम	तनुजा वासुनिक/अनिल कुमार वासुनिक	वार्ड क्र.58, उरला(पूर्व) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1163	1163	अमृत कुमार पटेल/राजा राम पटेल	शत्रुहन वर्मा/भागवत वर्मा,प्राधिकृत अधिकारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	वार्ड क्र.58, उरला(पूर्व) दुर्ग	विक्रय प्रमाण पत्र
1164	1164	पी.धर्मा राव/स्व.पी.अप्पा राव	सूरज कुमार कुमावत/राम प्रताप कुमावत	वार्ड क्र.52, बोरसी (दक्षिण) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1165	1165	अविनाश ठाकुर/शरदचंद्र हलदर ठाकुर	शरदचंद्र हलदर ठाकुर/स्व.हलदर ठाकुर	वार्ड क्र. 1, नयापारा दुर्ग	वसीयतनामा
1166	1166	धुपेश्वरी देशमुख/रूपेश्वर देशमुख	ताराचंद कुमावत/ रामप्रताप कुमावत	वार्ड क्र.52, बोरसी (दक्षिण) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1167	1167	त्रिलोका सिन्हा/कमल कुमार सिन्हा	अश्विन कुमार पटेल / पोपट लाल पटेल	वार्ड क्र.52, बोरसी (दक्षिण) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1168	1168	ललिता देवी साहू/टंकेश्वर कुमार	कामिनी वर्मा/अजय वर्मा	वार्ड क्र.52, बोरसी (दक्षिण) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1169	1169	शुभचंद्र जैन/स्व.पन्नालाल जैन	पन्ना जैन/सुन्दर लाल जैन,लाभचंद्र जैन/स्व.पन्ना लाल जैन	वार्ड क्र.41 केलाबाड़ी दुर्ग	हकत्याग पत्र
1170	1170	रानीदान जैन/हुकुमचंद्र जैन	गणेशमल कर्नावट/स्व.हुकुमचंद्र	वार्ड क्र.49बोरसी(पश्चिम) दुर्ग	दानपत्र
1171	1171	शमा बेगम/वाहिद अली	लाभचंद्र जैन/स्व.पन्ना लाल जैन	वार्ड क्र.41 केलाबाड़ी दुर्ग	दानपत्र
1172	1172	वहीदा रजा/स्व.मोहम्मद रजा	अरूणा मेहता/अनिशचंद्र मेहता	वार्ड क्र.45 पदमनाभपुर (पश्चिम)दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1173	1173	राजेन्द्र कुमार मौर्या/राम निहोर मौर्या	रामबली साहू/स्व.सहसराम साहू	वार्ड क्र.40 सुरना कालेज दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1174	1174	मोहम्मद खालिद कुरैशी/अबिद कुरैशी	जुलेखा बेगम/डॉ एफ.यू.फारूखी	वार्ड क्र.41 केलाबाड़ी दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1175	1175	रोहित कुमार गुप्ता/शीतला प्रसाद गुप्ता	दीनानाथ गुप्ता/रामरूप गुप्ता	वार्ड क्र.20 आदित्य नगर दुर्ग	पंजीकृत बयनामा
1176	1176	अहिल्या बाघ/कमल बाघ	मो.शकील कलीम,मो.शफकीक कलीम,मो.जीमल कलीम तीनों के पिता स्व.सिकंदर कलीम	वार्ड क्र.51 बोरसी(उत्तर) दुर्ग	पंजीकृत बयनामा

राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम दुर्ग

संकल्प के साथ आगे बढ़ता छत्तीसगढ़, जनकल्याण और विकास का बजट-चंद्रप्रकाश



कवर्धा (समय दर्शन)। नगर पालिका अध्यक्ष चंद्रप्रकाश चंद्रवंशी ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रस्तुत बजट वर्ष 2026-27 को विकासोन्मुखी एवं जनकल्याणकारी एवं संतुलित बजट बताया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट प्रदेश के हर वर्ग, किसान, युवा, महिला, व्यापारी एवं शहरी-ग्रामीण नागरिकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला है। नया अध्यक्ष श्री चंद्रवंशी ने कहा कि “संकल्प” थीम पर आधारित छत्तीसगढ़ का बजट वर्ष 2026-27 प्रशासन के समग्र एवं सतत विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है यह बजट केवल आय-व्यय का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य निर्माण का दृढ़ संकल्प है। नया अध्यक्ष श्री चंद्रवंशी ने बताया कि कवर्धा से खम्हरिया मार्ग तक सड़क उन्नयन व चौड़ीकरण कार्य हेतु 23 करोड़ का प्रावधान, जिले के पांडरिया में नालंदा परिसर का निर्माण, सुतियापाट से ठाठपुर तक पेयजल आपूर्ति हेतु 50 करोड़ का प्रावधान, इसी तरह नगरोत्थान योजना अंतर्गत नगर पालिका, नगर पंचायतों को शामिल करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, पेयजल व अन्य क्षेत्रों में कार्य किये जाने हेतु बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष श्री चंद्रवंशी ने कहा कि बजट में शिक्षा के क्षेत्र में नए विद्यालयों, उन्नयन कार्यों तथा डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रावधानों का स्वागत किया। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण, अस्पतालों एवं चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार को जनहित में महत्वपूर्ण कदम बताया। किसानों के लिए समर्थन मूल्य, कृषि योजनाओं एवं सिंचाई परियोजनाओं में वृद्धि बजट में प्राथमिक अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। यह बजट गांव, गरीब और किसान को सशक्त बनाने वाला है।

संकल्प नहीं शक का निराशाजनक बजट है- सीमा अनंत



कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष सीमा अनंत ने प्रस्तुत बजट को घोर निराशाजनक कहा है। उन्होंने बताया कि बजट में महिलाओं, युवाओं, किसान, मजदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की उपेक्षा साफ दिख रहा है। महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार, सुरक्षा के लिए कोई नीति नहीं है। युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इसके बाद भी नई भर्ती का न तो उल्लेख है और न ही रोजगार सृजन का कोई आधार दिख रहा है। जिलाध्यक्ष सुश्री सीमा ने कहा कि कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यहां तक रोजगार गारंटी योजना जिसे मोदी सरकार नए नाम वीबी जो राम जी के नाम से लाई है और राज्यांश 40 प्रतिशत रहना कहा गया है। छत्तीसगढ़ सरकार बजट में इसके लिए कोई राशि नहीं दिया है। इसका मतलब मनरेगा भी बंद होता दिख रहा। कुल मिलाकर यह बजट संकल्प नहीं शक का बजट है।

छत्तीसगढ़ का बजट, संकल्प विकास बजट- रामकुमार भट्ट



जिलापंचायत के पूर्व अध्यक्ष एवं वर्तमान जिलाध्यक्ष रामकुमार भट्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट को समावेशी, सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी और सर्वहितकारी बजट कहा है। उन्होंने यह बजट विकास की दिशा में सुशासन सरकार का सशक्त कदम बताया। हर वर्ग के लिए नए अवसरों का सृजन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और बजट प्रावधानों के माध्यम से हर स्तर पर विकास कार्य

मे तेजी आएगी, जिससे पूरे राज्य में गांव गांव तक विकास की किरणें पहुंचेंगी।

भ्रष्टाचार करने का संकल्प बजट- प्रशांत परिहार



कांग्रेस के युवा नेता प्रशांत परिहार ने बजट प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट सिर्फमायाजाल और मकड़जाल है। इससे प्रदेश के लोगों का कोई सरोकार नहीं है। श्री परिहार ने कहा कि पहला बजट का नाम गति रखा गया था, जो पूर्ण रूप से दुर्गति होने के बाद अब इस साल संकल्प नाम देकर बजट पेश किया गया और ये संकल्प इनका भ्रष्टाचार करने का संकल्प बनेगा। श्री परिहार ने कहा कि बजट में सभी वर्ग के लोग दुखी और निराश हुए हैं। बीस साल का सपना दिखाया गया है। कुल मिलाकर घोर निराशाजनक बजट है।

भाजपा ने बजट में फिर प्रदेशवासी और बेरोजगारों को ठगा- चोवाराम साहू



पूर्व मण्डी उपाध्यक्ष एवं कांग्रेस के युवा नेता चोवाराम साहू ने भाजपा सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने हर बार की तरह इस बार भी प्रदेशवासियों और युवाओं को ठगने का कार्य किया है। सरकार ने इस बार भी डोंगरगढ़-कवर्धा होते हुए उमलापुर रेल लाईन को बजट में हांसिए पर रख दिया है। सरकार अपनी योजनाओं में बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता योजना चालू रखने का दम भर रही है लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान तथा घोषणा नहीं है। जिससे बेरोजगार अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहे हैं। कुल मिलाकर सरकार का बजट सिर्फछलावा और प्रदेशवासी ठगो गए हैं।



संक्षिप्त-खबर

संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन के विद्यार्थियों ने किया तांदुला डैम का शैक्षणिक भ्रमण



राजनांदगांव। संस्कार सिटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठाकुरटोला द्वारा 22 फरवरी 2026, रविवार को डीएलएड प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। भ्रमण के तहत विद्यार्थियों को तांदुला डैम, जिला बालोद ले जाया गया। इस शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना तथा उनके बौद्धिक एवं सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करना था। भ्रमण के दौरान प्रशिक्षणार्थियों ने तांदुला डैम की संरचना, जल संग्रहण क्षमता तथा क्षेत्रीय कृषि एवं पेयजल आपूर्ति में इसकी भूमिका की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. गुप्ती कौर के मार्गदर्शन में प्रशिक्षणार्थियों एवं सहायक प्राध्यापकों ने भ्रमण में सहभागिता की। तांदुला डैम पहुंचकर विद्यार्थियों ने बांध की संरचना, जल संग्रहण प्रणाली और इसके क्षेत्रीय महत्व को करीब से समझा। इस अवसर पर प्राचार्य डॉ. गुप्ती कौर ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण से छात्र-छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ व्यावहारिक समझ भी विकसित करने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में समस्त प्रशिक्षणार्थी एवं सहायक प्राध्यापक उपस्थित रहे।

चीजगांव स्कूल में करवाया गया न्योता भोज



साजा (समय दर्शन)। साजा की प्राथमिक शाला एवं पूर्व माध्यमिक शाला चीजगांव में न्योता भोज का आयोजन किया गया। न्योता भोज का आयोजन सेवामार साहू के नाती एवं नातिन के विवाह कार्यक्रम के अवसर पर किया गया। न्योता भोज में मुख्य रूप से लड्डू, पापड़, सब्जी, दाल और चावल परीसा गया। मौके पर प्राथमिक शाला प्रधान पाठक लोकेश साहू, सहायक शिक्षक परमानंद तिवारी माध्यमिक शाला प्रधान पाठक तीजराम ठाकुर, शिक्षक अशोक साहू, दीपक लाल ठाकुर, संजय सरकार, स्वयं सेवी शिक्षिका मधु साहू समेत स्कूल के सभी विद्यार्थी ने न्योता भोज प्राप्त किया।

ग्राम मुसुवाडीह में हुआ भव्य संत समागम मेला महोत्सव



साजा (समय दर्शन)। साजा समीपस्थ ग्राम मुसुवाडीह में श्री सद्गुरु कबीर संत समागम मेला एवं सात्विक यज्ञ चौका आरती का आयोजन किया गया। भव्य मेला महोत्सव का आयोजन 21 फरवरी से 24 फरवरी तक किया गया। ग्रंथ प्रारंभ 21 फरवरी को दोपहर 3 बजे से शोभा यात्रा के साथ हुआ। 21 एवं 22 फरवरी को सत्संग ग्रंथ मंडली ग्राम हरडुवा और जागृति ग्रंथ मंडली कबीरधाम का आयोजन दोपहर 3 बजे से रात्रि 8 बजे तक हुआ। 23 फरवरी को महान श्री राजू दास साहेब एवं संत मंडली दामाखंडा वाले द्वारा भजन सत्संग प्रवचन, संध्या आरती एवं गुलाल उस्वव हुआ। संध्या 5:00 बजे पंथ श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहेब के करकमलों द्वारा चौका आरती सम्पन्न हुआ। चौका आरती व लेखन कार्य 21 फरवरी से 24 फरवरी तक सुबह से संध्या 4:30 बजे तक किया गया। मंगलवार 24 फरवरी को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भंडार कक्ष ग्राम धर्मनगरी मुसुवाडीह से संत मनिहार दीवान समाधि मंदिर स्थल तक निकाली गई। प्रतिदिन भोजन भंडारा भी होता रहा। ग्राम में इस तरह के पवित्र आयोजन को लेकर क्षेत्रवासियों में हर्ष का माहौल बना रहता है। मेला महोत्सव में दूर दराज से आगंतुकों की भीड़ उमड़ पड़ती है। विभिन्न प्रकारों की आकर्षक मय वस्तुओं ने मन को मोह लिया। तरह-तरह के झूले भी मेला को यादगार का पल बना देता है। आयोजन में साजा पुलिस की भी चौबीसों घंटा सहयोग मिलता रहा, जिससे आवागमन एवं विभिन्न प्रकारों की होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। संरक्षक पंथ श्री हुजूर 108 प्रकाशमुनि नाम साहेब आचार्य कबीर पंथ दामाखंडा, जिला-बलौदा बाजार रहे। आयोजन में समस्त क्षेत्रवासी एवं ग्रामवासी मुसुवाडीह का विशेष सहयोग रहा।

प्रदेश के युवाओं को समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट : अमन वर्मा

महासमुंद (समय दर्शन)। प्रधानमंत्री के विकसित भारत भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अमन वर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत वित्त वर्ष 2026-27 के 25 वां बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट ऐतिहासिक एवं प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने व समृद्धि की ओर अग्रसर करने वाला बताया है। अमन ने कहा कि जो 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर प्रदेश के विकास में चहुमुखी विकास लाने का प्रयास किया गया है। यह बजट

प्रधानमंत्री के विकसित भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होगा। बजट में युवाओं का बजट थीम के तहत उच्च शिक्षा, तकनीकी संस्थानों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान, व्यावसायिक परीक्षा मंडल की क्षमता वृद्धि एवं विस्तार के लिए 731 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्वामी



विवेकानंद उच्छृंखला योजना के लिए 100 करोड़ रुपये, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन के लिए 50 करोड़ रुपये तथा नए सीजीआईटी संस्थानों की स्थापना के लिए 38

करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहायता योजना के लिए 33 करोड़ रुपये और 36 इन्क्यूबेशन सेंटर एवं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत 25 नए महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये तथा रायपुर में मेगा परीक्षा केंद्र के लिए 25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आईआईटी में अधोसंरचना विकास के लिए 20 करोड़ रुपये और दुर्ग,

जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार एवं रायगढ़ के पांच शासकीय महाविद्यालयों में उच्छृंखला केंद्र स्थापना के लिए 15 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे विद्यार्थियों को शैक्षणिक सहयोग मिलेगा। सभी नालंदा पुस्तकालयों में करियर काउंसलिंग केंद्र स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपये तथा छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना के लिए 5 करोड़ रुपये की राशि तय

की गई है। यह बजट बता रहा है कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। अमन ने आगे कहा कि विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश कर 'संकल्प' थीम के साथ विकास का रोडमैप रखा। बजट में किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई, वहीं 18 वर्ष पूरे होने पर बालिकाओं को डेढ़ लाख रुपए दिए जाएंगे।

छत्तीसगढ़ के गौरव : आईआरएस शैलेंद्र देशमुख खेलो इंडिया विंटर गेम्स में दिखारंगे दम, गुलमर्ग में करेंगे अल्पाइन स्कीइंग

रायपुर (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ के लिए आगामी 'खेलो इंडिया शीतकालीन खेल-2026' गौरव के नए क्षण लेकर आ रहा है। राज्य के जांबाज अधिकारी और वर्ष 2008 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (IRS) अधिकारी शैलेंद्र कुमार देशमुख इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय मंच पर छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। वे 22 से 26 फरवरी तक गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) की बर्फीली वादियों में आयोजित होने वाली 'अल्पाइन स्कीइंग' स्पर्धा में अपनी चुनौती पेश करेंगे।



साहस और प्रशासन का अनोखा संगम

वर्तमान में रायपुर स्थित राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (NACIN) में निदेशक के पद पर पदस्थ श्री देशमुख 23 और 25 फरवरी को अपनी मुख्य स्पर्धाओं में भाग लेंगे। यह लगातार दूसरा मौका है जब वे राज्य की ओर से इस राष्ट्रीय मंच पर स्कीइंग करते नजर आएंगे। पारंपरिक रूप से छत्तीसगढ़ को शीतकालीन खेलों के लिए नहीं जाना जाता, लेकिन श्री देशमुख की निरंतर उपस्थिति ने राज्य को विंटर स्पोर्ट्स के राष्ट्रीय मानचित्र पर मजबूती से स्थापित कर दिया है।

मूल रूप से छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के ग्रामीण परिवेश से आने वाले श्री देशमुख केवल एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक बहुआयामी साहसिक खिलाड़ी भी हैं। वे

एक प्रमाणित पर्वतारोही, प्रशिक्षित स्क्वा डाइवर और लंबी दूरी के अनुभवी मोटरसाइकिल यात्री हैं। उनका मानना है कि अल्पाइन स्कीइंग जैसी स्पर्धाओं के लिए जिस उच्च गति, सटीक संतुलन और मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती है, वही गुण एक प्रशासनिक अधिकारी को संकट प्रबंधन और त्वरित निर्णय लेने में भी मदद करते हैं।

युवाओं के लिए मिसाल

सीमित संसाधनों और बिना किसी विंटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य से निकलकर गुलमर्ग की बर्फीली ढलानों पर तिरंगा लहराना, छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा है। उनकी यह उपलब्धि संदेश देती है कि यदि अनुशासन और दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो पृष्ठभूमि चाहे ग्रामीण हो या शहरी, किसी भी वैश्विक चुनौती को जीता जा सकता है। राज्य सरकार और खेल प्रेमियों ने उनकी इस भागीदारी को ऐतिहासिक बताते हुए उन्हें पदक जीतने के लिए अग्रिम शुभकामनाएँ प्रेषित की हैं।

'संकल्प से सिद्धि' की ओर छत्तीसगढ़: 2026-27 का बजट विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला - सुमित अग्रवाल

'नवा छत्तीसगढ़' की नींव रखेगा 2026-27 का 'संकल्प' बजट: सुमित अग्रवाल

जिला संयोजक सुमित अग्रवाल ने बजट को बताया तकनीक और परंपरा का बेजोड़ संगम, मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का जताया आभार



अंत्योदय और किसान खुशहाली का रोडमैप है बजट 2026-27: सुमित अग्रवाल

महासमुंद (समय दर्शन)। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 का 'संकल्प' बजट आधुनिक तकनीक और सांस्कृतिक परंपरा का एक बेजोड़ संगम है। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ महासमुंद के जिला संयोजक सुमित अग्रवाल ने इस बजट का पुरजोर स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के प्रत्येक नागरिक किसान, युवा, महिला और वनांचल वासियों के सर्वांगीण उत्कर्ष का एक सशक्त रोडमैप बताया है। सुमित अग्रवाल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के कुशल नेतृत्व और वित्त मंत्री की दूरदर्शी सोच की सराहना करते हुए इसे 'विकसित छत्तीसगढ़' की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग करार दिया।

प्रकाश डालते हुए कहा कि यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना और मानव संसाधन विकास पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकारी नीति को प्रदर्शन में, निवेश को परिणामों में और जनता की आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदलने की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 'गारंटी' को धरातल पर उतारने और वर्ष 2047 तक 'विकसित छत्तीसगढ़' के निर्माण की दिशा में एक निर्णायक कदम है।

आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक ने बजट को 'ज्ञान' (त-हू-ह) और 'गति' का संगम बताते हुए इसे कहा कि कृषक उन्निता योजना और सिंचाई परियोजनाओं के लिए किया गया भारी-भरकम प्रावधान सिद्ध करता है कि साय सरकार किसानों की समृद्धि के लिए संकल्पित है। बिना किसी नए कर के राजस्व बढ़ाना और किसानों को समर्थ पर इनपुट सब्सिडी देना वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के उत्कृष्ट वित्तीय प्रबंधन का परिचायक है।

भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुमित अग्रवाल ने बजट की व्यापकता पर

भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ जिला संयोजक सुमित अग्रवाल ने युवाओं के लिए कौशल

विकास, स्वरोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर दिए गए जोर की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'अटल निर्माण वर्ष' के तहत बुनियादी ढांचे में होने वाले निवेश से रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। साथ ही, 'महतारी वंदन योजना' और 'लखपति दीदी योजना' को नई गति देना प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत है। बजट में वनांचलों के विकास हेतु किए गए प्रावधानों को ऐतिहासिक बताते हुए भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सुमित अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए अभूतपूर्व कदम उठाए हैं। उन्होंने विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों (बहुलजत) के सर्वांगीण विकास हेतु पी.एम. जनमन योजना के तहत 720 करोड़ रुपये के विशाल प्रावधान को मील का पत्थर बताया। शिक्षा और अधोसंरचना के क्षेत्र में सरकार की गंभीरता को रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरबा में प्रदेशीय विद्यालय की स्थापना और प्रदेश भर में 25 नए एसटी छात्रावासों के लिए 75 करोड़ रुपये का आवंटन युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करेगा। सुमित अग्रवाल ने आगे कहा कि बस्तर एवं सरगुजा-जशपुर विकास प्राधिकरणों के माध्यम से स्थानीय विकास को प्राथमिकता देना क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक सरहनीय पहल है। इसके साथ ही, जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु 'जनजातीय सुर-गुड़ी स्टूडियो' की शुरुआत और बैगा-पुजारियों के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि सीधे तौर पर हमारी सांस्कृतिक धरोहर और परंपराओं के प्रति सरकार के सम्मान को प्रदर्शित करती है।

बजट में गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिला, अजा और आदिवासी समाज की उपेक्षा - विधायक चातुरी नंद

सरायपाली विधायक चातुरी नंद ने बजट को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना

सरायपाली नृपनिधि पाण्डेय (समय दर्शन) - विधायक चातुरी नंद ने वित्त वर्ष 2026-27 के राज्य बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश की मूल समस्याओं के समाधान के बजाय केवल घोषणाओं तक सीमित है। उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्र, महिलाओं, युवाओं तथा अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के लिए ठोस और प्रभावी प्रावधानों का अभाव स्पष्ट दिखाई देता है। विधायक नंद ने कहा कि यह संकल्प का नहीं, जनसमस्याओं की अनदेखी का बजट है जिसमें



महिलाओं, युवाओं, अनुसूचित जाति-जनजाति एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ठोस प्रावधान का अभाव है। विधायक चातुरी नंद ने कहा कि प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्थायी रोजगार सृजन की स्पष्ट कार्ययोजना बजट में नहीं दी गई है। केवल प्रशिक्षण और रोजगारों की घोषणा पर्याप्त नहीं है, जब तक कि रिक्त पदों की भर्ती, उद्योग स्थापना और स्थानीय रोजगार के अवसरों का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत न हो। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर भी बजट में कोई नया व्यापक आर्थिक पैकेज या ठोस योजना नहीं दिखाई देती। चुनाव के दौरान महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी, किंतु

जनजाति वर्ग के संदर्भ में कहा कि इन वर्गों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विशेष लक्षित योजनाओं और पर्याप्त बजट आवंटन की आवश्यकता थी, परंतु बजट में ऐसा कोई ठोस प्रावधान स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया। बस्तर और सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए भी समग्र विकास की ठोस रणनीति का अभाव दिखाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व बजट में एमएम की तर्ज पर 4 सिस्म और आईआईटी की तर्ज पर 4 सीआईटी खोलने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक इन घोषणाओं की जमीनी प्रगति स्पष्ट नहीं है। वर्तमान मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में शिक्षकों, डॉक्टरों और तकनीकी स्टाफ के कई पद रिक्त हैं। राजधानी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई



09 बोरी गुटखा जब्त, नमूने जांच हेतु भेजे गए

महासमुंद (समय दर्शन)। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने आज स्थानीय गंजपारा में औचक निरीक्षण कर बड़ी कार्रवाई की। टीम द्वारा फर्म मेसर्स मनभावन एजेंसी, गंजपारा, महासमुंद एवं फर्म मेसर्स हरीश जनरल स्टोर, गंजपारा, महासमुंद का आकस्मिक जांच किया गया। जांच के दौरान टीम ने मेसर्स मनभावन एजेंसी से 08 बोरी 'पान पसंद' (कुल 276 पैकेट) संभावित गुटखा जब्त

(अभिवृद्धि) किया। वहीं मेसर्स हरीश जनरल स्टोर से 01 बोरी 'पान पसंद' संभावित गुटखा वीज किया गया। कार्रवाई के दौरान सख्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रोशनी राजपूत एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी शंखनाद भोई द्वारा विधिवत नमूना संकलित किया गया। अभिहित अधिकारी श्री उमेश वर्मा ने बताया कि जब्त किए गए नमूनों को परीक्षण हेतु खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

अजीत जोगी युवा मोर्चा ने आबकारी आयुक्त और खनिज अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन, 7 दिनों का अल्टीमेटम



राजनांदगांव। आज अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम की उपस्थिति में शहर अध्यक्ष बिलाल सोलिन खान और जिला महासचिव ऋषभ रामटेके के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जॉइंट कलेक्टर प्रकाश टंडन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया।

शमसुल आलम ने कहा कि राज्य शहरी विकास अधिकरण द्वारा 2025 में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि डिस्ट्रिक्ट पानी पाउच को बंद किया जाएगा, जो कि आबकारी विभाग के आदेश के तहत भी था। बावजूद इसके, शहर में पानी पाउच बंद जा रहे हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा, खनिज विभाग द्वारा ग्राम सिंगोला के करमतरा क्षेत्र में रहे अत्यधिक उत्खनन को लेकर ग्रामीणों द्वारा पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर जोगी कांग्रेस ने सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है।

इसके साथ ही, शमसुल आलम ने होली के दिन शराब दुकानों की बंदी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और आबकारी आयुक्त आर. संगीता से इस पर विचार करने की अपील की। जॉइंट कलेक्टर टंडन ने इन दोनों मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मौके पर अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला महासचिव ऋषभ रामटेके, विधानसभा अध्यक्ष नमन पटेल, शहर अध्यक्ष बिलाल सोलिन खान, मुकेश साहू, अनवर खान, शुभम भालाधारे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।

अजीत जोगी युवा मोर्चा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष शमसुल आलम की उपस्थिति में शहर अध्यक्ष बिलाल सोलिन खान और जिला महासचिव ऋषभ रामटेके के नेतृत्व में मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जॉइंट कलेक्टर प्रकाश टंडन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दो प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित किया गया। शमसुल आलम ने कहा कि राज्य शहरी विकास अधिकरण द्वारा 2025 में सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए गए थे कि डिस्ट्रिक्ट पानी पाउच को बंद किया जाएगा, जो कि आबकारी विभाग के आदेश के तहत भी था। बावजूद इसके, शहर में पानी पाउच बंद जा रहे हैं, जिस पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई है। इसके अलावा, खनिज विभाग द्वारा ग्राम सिंगोला के करमतरा क्षेत्र में रहे अत्यधिक उत्खनन को लेकर ग्रामीणों द्वारा पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इस मुद्दे पर जोगी कांग्रेस ने सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। इसके साथ ही, शमसुल आलम ने होली के दिन शराब दुकानों की बंदी की मांग करते हुए मुख्यमंत्री और आबकारी आयुक्त आर. संगीता से इस पर विचार करने की अपील की। जॉइंट कलेक्टर टंडन ने इन दोनों मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही का आश्वासन दिया। इस मौके पर अजीत जोगी युवा मोर्चा के जिला महासचिव ऋषभ रामटेके, विधानसभा अध्यक्ष नमन पटेल, शहर अध्यक्ष बिलाल सोलिन खान, मुकेश साहू, अनवर खान, शुभम भालाधारे सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद थे।